discussion in the House I would have come back from my foreign visit where I am going to make my efforts in search of oil and I hope that the goodwill and the good wishes of this honourable House will be with me in my efforts to do the needful.

13.20 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND EIGHTEENTH AND HUNDRED AND TWENTY-THIRD REPORTS

SHRI P. V. NARASIMHA RAO (Hanamkonda): I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

(1) Hundred and eighteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Seventy-first Report relating to Posts and Telegraphs.

(2) Hundred and twenty-third Report on Paragraph 47 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1976-77, Union Government (Civil), Revenue Receipts, Volume II, Direct Taxes on Voluntary Disclosure of Income and Wealth Scheme, 1975 relating to the Ministry of Finance (Department of Revenue).

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

EIGHTEENTH AND NINETEENTH REPORTS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:

(1) Eighteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Seventh Report of the Committee on Central Inland Water Transport Corporation——Objectives and River Services.

(2) Nineteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Ninth Report of the Committee on Central Inland Water Transport Corporation——Mismanagement in Organization, Administration and Financial Matters.

13.22 hrs.

DEMAND FOR GRANTS, 1979-80—*contd.*

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

Shri Manoranjan Bhakta.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Deputy-Speaker, Sir, one of the objects of the Home Ministry is to provide good administration for the Union Territories and their proper development. As I was saying, what type of Government has been provided to the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands!

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you had finished your speech yes-

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I will conclude just in a few minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: It is absolutely a bad type of Government provided there with iron curtain. When a Member of Parliament duly elected from that constituency is not permitted to use loudspeaker,

[Shri Manoranjan Bhakta]

you can well understand the type of Government existing there. As a Member of Parliament, I want to meet my people and go to different islands for this purpose. Obstruction is created so that I cannot go. The tour programmes had to be cancelled. You can well imagine the type of Government there.

Sir, the problems in the Islands are mounting up. The unemployment problem is very acute there. The number of unemployed youth is increasing and there is no employment potential in the Union Territory. The poor and weaker sections of people have been claiming for house sites; they are asking for surplus agricultural land to be allotted to them, but no action has been taken on these issues. That is why, I had submitted a 90-point charter of demands to the Prime Minister. A month was given to them for consideration, but nothing was done. Ultimately, I had to go on fast which continued for 15 days. When the hon. Prime Minister visited that place, or the other Ministers went there, they had not the elementary courtesy to send me a letter about their visit. I am the lone Member of Parliament representing this Union Territory. Many hon. Members from this side and that side who have visited that territory, would have their own experience of the type of administration that exists there.

I know, the hon. Minister of State for Home Affairs, Shri Dhanik Lal Mandal comes from a very poor and down-trodden class and he is well aware of the problems of the people there and how they have been curbing the democratic rights of the people. In the question hour, I showed a photograph of three old ladies who had lost their fingers on account of the atrocities committed on them.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have no other forum to ventilate the grievances of our people except this House. It is only during the discussion on the Demands for Grants of the Home Ministry, when I can ventilate the grievances of the people of that area. I want to appeal to the Hon. Minister not to be cruel to us and not to have a partisan attitude. You should have a fair attitude towards this small and remote Union Territory, and do justice to us. You must provide us with some sort of a democratic set up. You must see that only those officers who are unwanted in Delhi or other parts of the country are not shunted there. That is my request.

I hope, the hon. Minister will definitely look into these and other problems of this Union Territory very carefully and sympathetically.

श्री श्रीकृष्ण सिंह (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह विभाग की मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

गृह विभाग की तरफ से जो बुलेटीन निकले हैं उन में बतलाया गया है कि विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिये कितनी सारी कार्यवाहियां की गईं, पिछड़े वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, हरिजन और जन-जातियों के लिए भिन्न-भिन्न आयोग, प्रधान मंत्री की चिन्ता ला एण्ड आर्डर के बारे में और उस के लिए विपक्ष के लोगों के साथ जो बैठकें हुईं, मुख्य मंत्रियों के साथ जो बैठकें हुईं और ये राव जो कार्यवाहियां हुई हैं, उन का विवरण उन में दिया हुआ है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध कुछ बढ़ रहे हैं कुछ मात्रों में और ये संगठित अपराध का रूप ले रहे हैं । बार बार उन की पुनरावृत्ति हो रही है । इन अपराधों के चरित्र को देखने से लगता है, कि इस की गहराई में अध्ययन करने की जरूरत है कि कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से आधारभूत कारण हैं, जिन के चलते ये सब अपराध घटित हो रहे हैं, घटित होने में मदद पहुंचाते हैं । हम पुलिस संस्थान से अपेक्षा रखते हैं कि वे अपराधों की रोक थाम करेंगे । उन का विश्लेषण करना भी उन की जिम्मेदारी है लेकिन पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनःस्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या वजह है कि पुलिस और जनता के बीच में जो एक रिश्ता होना चाहिये, आज वह रिश्ता नहीं है । बल्कि एक भय और अविश्वास का रिश्ता है । भय और शंका से ये मुक्त नहीं हैं। आम नागरिक आज भी यह समझता है कि

पुलिस प्राय: जनता के प्रति उदासीन रहती है और उस के प्रति शंका की भावना आम नागरिक के मन में है । पिछले 30 वर्षों में क्या कोई कोशिश कांग्रेस के शासन में की गई कि पुलिस और जनता के बीच में जो खाई है, जो दूरी है, उस को कम किया जाए और दोनों की मन: स्थिति में परिवर्तन लाया जाए ? क्या इस के लिये कोई कार्यवाही की गई ? गहराई से अध्ययन करने से पता लगेगा और सरसरी तौर पर भी पता लगेगा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है । पुलिस का जो वर्तमान मूलभूत ढांचा है, वह आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम को निरर्थक लगता है, अक्षम लगता है । आज के समय की जो चुनौती है, उस को वह स्वीकार नहीं कर सकता । पुलिस का यह चरित्र शायद ब्रितानी साम्राज्य से विरासत में मिला है, जिस में सुधार करने की जरूरत है । पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ ? हम अपनी इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इस ने पहली बार राष्ट्रीय पुलिस आयोग बिठाया । जो आयोग 1947 में ठीक आजादी के बाद, बैठ जाना चाहिए, वह नहीं बैठा था । आजादी के बाद पुलिस के चरित्र में, उस की भूमिका में परिवर्तन लाने के लिए 1947 के बाद, आजादी के ठीक बाद आयोग बैठ जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ । 30 साल के बाद हम इस सरकार को धन्यवाद देते हैं कि पहली बार राष्ट्रीय पुलिस आयोग का इस ने गठन किया है । इस चीज को देखने के लिए कि पुलिस की भूमिका क्या हो, इस का चरित्र क्या हो और इस को ठीक ठाक करने के लिए क्या किया जाय । आज तो एक आम आदमी पुलिस को बेसरोकार और निरर्थक मानता है और यह समझता है कि पुलिस और अपराधी के बीच में सांठ-गांठ है और उसकी वजह से अपराधी फल-फूल रहे हैं । पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे भी अपनी अक्षमता को समझ रहे हैं और वे बेचारे भी चिन्तित हैं कि पुलिस में कैसे सुधार हो, वे भी परेशान हैं । और स्थिति यह है कि आज रूल आफ़ ला नहीं है बल्कि रूल आफ आर्डर चल रहा है । इंगलैंड में सर राबर्ट मार्क जो पुलिस के भूतपूर्व आयुक्त थे लन्दन के, उन्होंने कहा था कि पुलिस जनता और कानून की सेवक है और किसी अन्य की नहीं यहां तक कि सरकार की भी नहीं । लेकिन यहां पर पुलिस आयुक्त क्या इस बात को मानने को तैयार है ? यहां पुलिस इस्तेमाल हो रही है राजनीतिक दलों, सत्ताधारी दल से । पिछले 30 सालों में ऐसा ही चलता रहा है यहां के पुलिस आयुक्त में इतना दम नहीं इस बात को कहने का कि हम किसी के भी सेवक नहीं हैं, सरकार के भी नहीं हैं, हम तो कानून के प्रति जिम्मेदार हैं, अदालत के प्रति जिम्मेदार हैं, लन्दन में वहां की संसद को ही यह अधिकार है कि वह पुलिस आयुक्त को सस्पेंड कर सके या कोई और दूसरी कार्यवाही करे, पुलिस की भूमिका के बारे में या पुलिस की व्यवस्था के बारे में । हमारे यहां ऐसा नहीं है । इस का कारण क्या है ? 1861 का जो भारतीय दंड संहिता कानून है, उस में कहीं भी 'सेवा' का उल्लेख नहीं है और हम को ऐसा लगता है कि हम एक नई आधुनिक लड़ाई पुराने हथियारों के बल पर लड़ रहे हैं । पुलिस को हमने वही भारतीय दण्ड संहिता दी है जिस में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उसी हथियार पर उस से हम कहते हैं कि तुम अपराध का विश्लेषण करो, अपराधी को पकड़ो और अपराध की रोकथाम करो । यह हारे हुए युद्ध जैसी बात है ।

सब से पहले 1859 में पुलिस आयोग बना था । हिन्दुस्तान में जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस पराजय के दो वर्ष के बाद भारत में यह आयोग बना और दूसरा आयोग लार्ड कर्जन ने 1902 में बिठाया था । उस पुलिस आयोग ने पता लगाया था कि 1859 वाले आयोग में बहुत सारी खामियां थीं और उसे अंग्रेजों ने इस उद्देश्य से बिठाया था कि हिन्दुस्तान में पुन: हमें सेना पर निर्भर न रहना पड़े और आंतरिक शांति के लिए पुलिस तंत्र को ऐसा विकसित किया जाए कि देश में कभी विद्रोह न हो और अगर हो तो पुलिस तंत्र से उसका मुकाबला कर उसे समाप्त कर दिया जाए । इसी दृष्टि से यह आयोग बना था । लार्ड कर्जन थे एक हद तक लोकतांत्रिक मगर वे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि थे, इसलिए वे चाह कर भी कुछ नहीं कर सके । 1902 का पुलिस आयोग भी कोई ज्यादा काम नहीं कर पाया । हमारे यहां के जो एक भूतपूर्व पुलिस अफसर श्री के० एम० रुस्तम साहब हैं उनका भी यही कहना है कि हमारे यहां की पुलिस का जो कांस्टेबल है, वह सब से बड़ा दलित वर्ग है । उसको बहुत कम तनख्वाह मिलती है । उस का काम जनता की सेवा न कर के, बल्कि अंग्रेजों ने जो सोचा था कि ऐसी सस्ती पद्धति का विकास करो जिससे शासन तंत्र चल सके । लार्ड कर्जन के सामने आयोग ने दो सिफारिशें की थीं—एक तो यह कहा कि पुलिस में शिक्षित आदमियों को लाना चाहिए और अच्छा वेतन दे कर लाना चाहिए । मगर अर्थ के कारण, फण्ड के कारण इस सुझाव को नहीं माना गया । दूसरा सुझाव था कि अनपढ़ आदमियों को लाना चाहिए जिनके सामने कोई विवेक और जिम्मेदारी न हो । ऐसे ही सिपाहियों को ले कर इस पुलिस तंत्र का विकास किया गया और आज भी वही चला आ रहा है ।

पुलिस तंत्र में दक्षता और ईमानदारी लाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि निचले कर्मचारियों की सेवा स्थिति में सुधार हो । यह सुधार तभी संभव और सार्थक होगा जब सारा ध्यान नीचे के लोगों पर केन्द्रित किया जाए । पुलिस दल में 80 परसेंट सिपाही होते हैं । इस संस्था का जो आचरण है वह इन्हीं लोगों का आचरण होता है और उसी का प्रभाव जनता पर पड़ता है । अगर इन लोगों का सिपाही आचरण और व्यवहार खराब है तो जनता समझती है कि पुलिस का आचरण खराब है । पिछले तीस वर्षों में क्या शांति व्यवस्था में कोई ऐसा काम हुआ है कि जिस से

[श्री श्रीकृष्ण सिंह]

यह पता चल सके कि इस विभाग की स्थिति में सुधार किया गया हो ? पुलिस बिचारी बराबर जूझती रही है शांति व्यवस्था और विधि-व्यवस्था को संभालने में वह तनावों का शिकार है। उसकी स्थिति को आप दिल्ली में ही देख लीजिए। पुलिस के सिपाही को 240 रुपये महीना मिलता है जो कि एक अन-स्किल्ड लेबर, अकुशल लेबर की तनख्वाह से भी कम है। उसे 12-12 घंटे तक ड्यूटी पर खड़ा रहना पड़ता है। उसे अपने लिए नाममात्र का टाइम मिलता है। उसे नाममात्र का भत्ता मिलता है जो कि डेढ़ रुपये रोज है। उस के पास जो सामान है, जीप गाड़ी यंत्र वगैरह: वे सब इतने पुराने और आऊट मोडिड हैं कि उन से काम नहीं चल सकता। क्या आप इस के बल पर विधि व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए।

लेकिन क्या इस से पुलिस का रूपांतरण हो जाएगा। उसकी भूमिका को भी बदलना होगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाना होगा। ब्रिटेन में, लन्दन में पुलिस आयुक्त को संसद ही हटा सकती है। वह कानूनी अदालतों का आदमी है। वह किसी मंत्री या राजनीतिक दल के आदेश पर काम नहीं करता। भारत में इसका इस्तेमाल सत्ताधारी दल अपने काम के लिए करता है। हम चाहते हैं कि अगर इसे जनता का सेवक बनाना है तो पुलिस की भूमिका को बदलना होगा। केवल उसकी तनख्वाह बढ़ाने और उसके साधन बदलने मात्र से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी भूमिका को भी बदलना होगा। तभी जा कर जनता का सेवक हम उसको बना सकते हैं। पुलिस द्वारा मांग की जाती है कि हमारा अधिकार बढ़ाया जाए। हम देखते हैं अधिकार बढ़ाने से व्यक्ति भ्रष्ट भी हो जाता है। हां राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। राजनीतिक लोग इस बात में खुश होते हैं कि फलां का हम ने ट्रांसफर करा दिया, उसको बदलवा दिया। यह काम की बंद होना चाहिए। लेकिन आज यह भी देखा जाता है कि बाहर के आदमी, राहत महसूस करते हैं, राजनीतिक दल के आदमी से। पुलिस आंतक से राजनैतिक लोग ही रक्षा करने में सहायक हैं। कहीं गाड़ी में चले जाइये, चैक पोस्ट्स बनी हैं, वहां नियुक्त पुलिस कर्मचारी खुल कर ट्रक वालों से पैसा ले रहे हैं। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल का आदमी रहे तो पुलिस वाले घबड़ा जाते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि पुलिस अपना चरित्र और भूमिका बदले। साथ ही राजनीतिक दल के लोग भी पुलिस के मामले में दखलंदाजी न करें, उनको इस हस्तक्षेप से आजादी मिलनी चाहिये।

3 अगस्त, 1978 को आन्तरिक सुरक्षा कानून रद्द किया गया, नजरबन्दों की रिहा किया गया। 2,568 नक्सलवादियों की रिहाई हुई। लेकिन उसकी स्याही सूख भी नहीं पायी थी, मध्य प्रदेश में मिनि मीसा लगाया गया, गुंडा अधिनियम बनाया गया। बिहार में अपराध नियंत्रण अध्यादेश 30 सितम्बर को लागू किया गया। यह देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन है बहुत खोटा। जिलाधिकारियों को अधिकार है कि जिसको चाहें उसको उठा कर बन्द कर दें। कमिश्नर को अधिकार दिया गया है अपील सुनने का। राज्य स्तर पर कोई रिव्यू बोर्ड नहीं है, न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार नौकरशाही के हाथ में नागरिकों की आजादी बन्धक रख दी गई है। जिस जहरीले दिमाग ने मीनी मीसा जैसी चीज बनायी है उस दिमाग को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। यह तानाशाही का द्योतक ही माना जायेगा। आपातकाल के प्रवर्तकों के बारे में हम बराबर कहते हैं कि उनका दिमाग तानाशाही था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार में जो लोग ऐसे कानून बना रहे हैं वह एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनका दिमाग भी उतना ही जहरीला है। भले ही स्लोगन लगाने के लिये कह दें कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ब्रिगेड के लोग तानाशाह थे, लेकिन हमारा भी दिमाग उतना ही संकुचित है। क्या आई०पी०सी० में सुधार कर के हम असामाजिक तत्वों को काबू में नहीं कर सकते हैं ? कर सकते हैं। 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो संशोधन हुआ उसके अनुसार अगर अपराधी 60 दिन तक जेल में रहता है और पुलिस अपनी रिपोर्ट नहीं भेजती है तो कोर्ट को अधिकार है कि 61वें दिन उसको जमानत पर छोड़ सकती है। आज होता यह है कि बहुत सारे अपराधी लोग पुलिस के यहां पैरवी करते हैं कि हमारी रिपोर्ट पुलिस न भेजे ताकि कोर्ट उनको जमानत पर 61वें दिन छोड़ दे। क्यों नहीं इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन किया जाता है ? और डकैती तथा मर्डर केसेज में इस को लागू नहीं होना चाहिए।

अभी प्रधान मंत्री जी ने मुख्य मंत्रियों की कानफ्रेंस बुलायी थी जिसमें कहा गया कि 1973 में जो सेपरेशन आफ़ जुडिशियरी और ऐग्जीक्यूटिव हुआ था, कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह सवाल उठाया कि यह गलत काम हुआ था वह ठीक नहीं था। फिर से ऐग्जीक्यूटिव के हाथ में अधिकार देना चाहिये कि वह मागनीजेन्स का अधिकार ले ले। स्टेट्समैन ने इस पर लेख लिखा है, चुटकी ली है। जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रवर्तक हैं। लेकिन जनता पार्टी के कुछ मुख्य मंत्रियों का यह हाल है कि आज वह चाहते हैं कि इस सेपरेशन को समाप्त करना चाहिये। कार्यकारी को अधिकार लौटाना चाहिये।

हरिजनों पर अत्याचार की बहुत कहानियां गायी जाती हैं। प्रैस के द्वारा भी धुआंधार प्रचार होता है। असली बात यह है कि हरिजनों में प्रतिरोध की ताकत बढ़ रही है, उनके अन्दर जो हजारों सालों की हीन भावनायें थी वह घट रही हैं और उनमें भी टक्कर लेने की स्थिति पैदा हो रही है। ऊंची जातियों के दिमाग में जो अहंकार की भावना थी कि हम से यह लोग छोटे हैं आज हरिजन वर्ग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। कंझावाला के सवाल पर जो प्रदर्शन हुआ वह मध्यम जातियों की उभार का उदाहरण है। लेकिन आज सारी पृष्ठभूमि में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि तीन स्टेजेज आती हैं। एक होती है पराधीनता की स्टेज, इसमें जब लोग विद्रोह करते हैं तो उनको बागी कहते हैं, अनुशासनहीन कहते हैं। छात्र समाज और

श्रमिक वर्ग को कहा जाता है कि अनुशासन तोड़ने वाले हैं। लेकिन पराधीनता के विरुद्ध जो लड़ाई है, उसको हम विद्रोह मानते हैं। चाहे वह विदेशी पराधीनता हो या देशी पराधीनता। पराधीनता के खिलाफ़ लड़ाई को विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। पराधीनता जब मिट जाये, विद्रोह जब सफल हो जाये, तो जो स्टेज पहले आयेगी वह स्वच्छन्दता की स्टेज होगी और दूसरी स्टेज स्वतंत्रता की होगी। आज हम जिस संक्रमण स्टेज से गुजर रहे हैं, यह कोई स्वतंत्रता की स्टेज नहीं है। आज श्रमिक वर्ग, चाहे कोई भी क्लास हो, वह अपने हक के लिये लड़ रहा है, छात्र भी लड़ रहे हैं। जहां देखिये वहां स्वच्छन्दता की मनोवृत्ति है, आज हम ट्रांजीशन के पीरियड में हैं। स्वतंत्रता तो विवेक से आती है, जब हम समझेंगे कि हमारी इस कार्यवाही में समाज और राष्ट्र का हित होगा।

रेल में बिना टिकट सफर करना, टी०टी० को पीटना, मार-पीट करना, होली, ईद, बकरीद आदि किसी त्यौहार में कोई तनाव हो जाये तो रेल गाड़ी का गद्दा उखाड़ना, पत्थर फेंकना वगैरह यह सब स्वच्छन्दता है, यह स्वतंत्रता हरगिज नहीं है। मगर यह स्टेज है और कुछ काल तक रहेगी। जब 19 महीने इस देश में पराधीनता रही, 19 महीने के पहले पूरे दशक तक तैयारी चल रही थी, यह नहीं कि 25 जून को अपने आप सूरज उगा तानाशाही का, ऐसी बात नहीं है। 25 जून, 1975 के पहले देश में तैयारी हो रही थी, देश तानाशाही की तरफ़ बढ़ रहा था, देश का अर्थ-तंत्र, राजनैतिक तंत्र और प्रशासन तंत्र सब तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे। 25 जून, 1975 से 19 महीने तक देश पराधीन रहा और लोग बन्द बोतल में डूबे रहे जो सफोकेशन की स्थिति थी। आज स्वच्छन्दता का स्टेज है। हमारी सरकार को इस बात को नजरन्दाज नहीं करना चाहिये। यह बात मानकर नहीं चलना चाहिये कि आज छात्रों में अनुशासनहीनता है या मजदूरों और श्रमिकों की अकारण हड़ताल होती है। कहीं वह अगर बोनस के लिये लड़ते हैं या राष्ट्र के हित को नहीं देखते हैं तो यह स्वाभाविक है, यह लोग लड़ेंगे। इस तथ्य को सरकार को ध्यान में रखना चाहिये। आज सभी मुद्दों पर हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत चिन्तित हैं, कभी हरिजनों की मीटिंग में जाते हैं और कभी विपक्षियों के साथ मीटिंग करते हैं। चाहे अलीगढ़ का दंगा हो या कहीं का हो, यह ठीक है कि अल्पसंख्यकों के दंगों की तादाद घटी है। यह सब काम प्राइम मिनिस्टर की मात्र चिन्ता को व्यक्त करते हैं। लेकिन हमारा काम निषेधात्मक नहीं, नकारात्मक कार्यवाही नहीं, हमारा कुछ काम रचनात्मक होना चाहिये।

हिन्दू-मुस्लिम एकता की खाई को पाटने के लिये पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ? जो हीन भावना है, मुसलमान अपने को सौतेला भाई मानते हैं। पिछली सरकार ने उन्हें 30 बरसों तक एक-दूसरे की पीठ ठोंककर लड़ाया, दोनों के बीच की खाई को नहीं पाटा। इस सरकार की हिन्दू-मुस्लिम दोनों को, मन की खाई को, अल्प-संख्यकों और बहुसंख्यकों के मन की खाई के खार को दूर करने और पाटने का काम करना चाहिये। यह काम कई तरीकों से हो सकता है। जैसे भाषा का सवाल है, संस्कृतनिष्ट भाषा की जगह हिन्दुस्तानी भाषा जिसमें उर्दू, बंगला, तामिल शब्द रहें का इस्तेमाल करें। जैसे ऐतिहासिक अशोक चक्र को चलाया उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में शेरशाह ने पेशावर से हावड़ा तक लम्बी सड़क बनाई, उसे अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक रोड का भद्दा नाम दिया। हम क्यों नहीं उसका नाम बदलकर शेरशाह पथ रखते हैं? शेरशाह हमारे देश के पुरखे रहे हैं। हमें ऐसे बहुत काम करने चाहिये। इससे हम हिन्दू-मुस्लिम एकता जिन्दा कर सकेंगे, दोनों के मन की खाई को निकालने का काम कर सकेंगे। हमें इस सम्बन्ध में रचनात्मक कार्यवाही करनी चाहिये। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वह सराहनीय है, मैं चाहता हूं इससे आगे बढ़कर काम किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल): उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर जुल्म और सितम की कहानी इस बार भी सुनने में आई। माननीय सदस्यों ने इस बारे में बड़ी चिन्ता जाहिर की। माननीय सदस्य, डा० कर्ण सिंह, ने यहां तक कहा कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का ताना-बाना ढीला हो रहा है सीमान्त पर ढीला हो रहा है, चाहे वह उत्तर-पूर्व सीमांत हो या उत्तर-पश्चिम सीमांत हो। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर भी जातीय विद्वेष है, जातीय दंगे हो रहे हैं, हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, जिस से हमारी नेशनल लाइफ़ का फ्रेब्रिक, राष्ट्रीय जीवन का ताना बाना, ढीला हो रहा है, और यह हमारे लिये खतरे की बात है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह सवाल, जिस को हम हरिजन या आदिवासी सवाल कहते हैं, हमारे हृदय के बहुत निकट है। हम इस सवाल से बहुत ही चिन्तित हैं और इस का हल करने के लिए हम जितना भी प्रयास, कोशिश, कर सकते हैं, वह हम कर रहे हैं। अत्याचारों की ये घटनायें यद्यपि राज्यों का विषय हैं, क्योंकि विधि-व्यवस्था कायम करना, और विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को सजा देना राज्यों का विषय है, फिर भी जहां तक हरिजनों और आदिवासियों के उत्पीड़न का सवाल है, हम बराबर राज्यों से सम्पर्क बनाये रखते हैं, स्थिति पर पूरी निगरानी रखते हैं, और जहां कहीं भी हम समझते हैं कि राज्य सरकारों को सलाह या परामर्श देने की जरूरत है, या राज्य सरकारों की ओर से जहां कहीं भी सहयोग के लिए मांग होती है, तो हम उस पर अवश्य विचार करते हैं।

इस विषय में समय समय पर जो आदेश या डायरेक्शन्स दिये गये हैं, उन सब को रीव्यू करने क

[श्री धनिक लाल मण्डल]

लिए, उनका जायजा लेने के लिए, हमने पिछले दिनों राज्यों का दौरा किया, और राज्य सरकारों के साथ मिल-बैठ कर हम ने उन सारे आदेशों या डायरेक्शन्ज पर चर्चा की, और उन की कठिनाई क्या है, और कहां तक हम उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं, इस पर हम ने उन की राय का या अनुभव को जानने की कोशिश की ।

मैं एक उदाहरण दूंगा । हाल में मैं बिहार गया था—क्योंकि बिहार की घटनाओं से माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हो उठे थे—, और बिहार में जो भी एट्रासिटी-प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन के अफ़सरों को हम ने बुलाया था, और राज्य सरकार के अफ़सरों और मंत्रियों के साथ—मुख्य मंत्री भी उन में शामिल थे—हम ने विचार किया था। हम ने वहां कहा था कि इन दस जिलों में आप दस हजार होम गार्डज की तत्काल भर्ती कर लें, जिसका खर्चा केन्द्रीय सरकार 50 : 50 बेसिस पर उठायेगी —एक जिले में एक हजार होम गार्डज की भर्ती कर लें, जिन में अधिकांश हरिजन हों। वैसे ही इन जिलों में पुलिस को मजबूत करने के लिए, उन को आधुनिक साज-सज्जा देने के लिए, उस को द्रुतगामी सवारी देने के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी हम ने उन को रुपये की मंजूरी दे दी और उनकी और जो भी कठिनाइयां होती हैं उन को हम ने उनसे सुना, उनका जायजा लिया और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं ।

मैं यह कह रहा था कि हरिजनों पर जो ये जुल्म होते हैं उन की रोकथाम के लिये शार्ट टर्म में, जल्दी से जल्दी हम क्या कर सकते हैं इस पर हम बराबर ही विचार कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम हैं यह हम अवश्य उठाते हैं । राज्य सरकारों की ओर से हम को अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है, मिल रही है, और राज्य सरकारों का सहयोग मिल रहा है । यद्यपि अभी भी हमारे लिए यह कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि जो अत्याचार हो रहे हैं उस में बहुत कमी हो गई है या उस का उस पर प्रभाव पड़ा है लेकिन इस का प्रभाव होगा, यह मेरा विश्वास है । मैं माननीय सदस्यों से दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े हैं एट्रासिटीज के जिससे माननीय सदस्य बहुत चिन्तित होते हैं, इस के पीछे जा कर देखें तो इस के लिए जो सब से बड़ा कारण है वह है आर्थिक । माननीय सदस्यों ने कहा कि ये जो हरिजनों पर जुल्म और सितम होते हैं चाहे व्यक्ति की ओर से हों चाहे सामूहिक हों, जाति की ओर से हों, दोनों तरफ से होते हैं लैंड-लार्ड भी करता है और कास्ट भी, जाति भी करती है। यह सोशल और एकोनामिक दोनों हैं . . .

श्री बही लाल (बिजनौर): सोशल कम है एकोनामिक ज्यादा है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : हां, वही मैं कह रहा हूं । मैं दोनों कह रहा हूं । आप सुनिए। हम को बीच में रोकिएगा तो हमारा प्रवाह टूट जायगा ।

मैं यह कह रहा था कि ये जो घटनाएं होती हैं उन के पीछे जो कारण है वह कारण यह है कि हरिजन अब जागृत हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए हैं और अपने अधिकारों को लेने के लिए अब वह प्रयास कर रहे हैं । एसर्ट कर रहे हैं। इस से जो संघर्ष पैदा होता है इस संघर्ष में हरिजन कमजोर होते हैं और इसलिए यह बेमेल लड़ाई हो जाती है । जैसे राम विलास पासवान जी ने कहा है कि यह बेसेल लड़ाई हो जाती है, एक तरफ तो कमजोर लोग खड़े होते हैं, दूसरी तरफ मजबूत लोग खड़े होते हैं , इन दोनों के बीच में हरिजन जो कमजोर होते हैं, मारे जाते हैं । पीटे जाते हैं, सताये जाते हैं । यह कारण है कि हरिजनों पर इतना जुल्म हो रहा है और यह बात सही है कि जो घटनाएं हो रही हैं उस को यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इस दृष्टि से देखें तो यह जो बढ़ती हुई रेखाएं हैं वह इसलिए हैं कि अब ये सामाजिक और आर्थिक संघर्ष अधिक होने लग गए हैं यद्यपि इन संघर्षों में हरिजन कमजोर होने के नाते पिटते हैं, यह बात सही है । इसलिए अभी जो चार्ट कुछ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है इस का कारण यह है कि ये सामाजिक और आर्थिक संघर्ष बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते जायेंगे जैसी कि आशा है । जो माहौल है, जो वातावरण है, जो आज की दुनिया है उस को देखते हुए और जो आज की हमारी मान्यताएं हैं, संस्कृति है, जो जनतंत्र का वातावरण है, इन सारी चीजों को लें तो यह अवश्यंभावी है कि संघर्ष बढ़ेंगे । इस संघर्ष में हरिजन कमजोर न रहें, उन को मजबूत बनाया जाये जिस से वे पिटें नहीं इस के लिये सरकार को क्या उपाय करना चाहिये यह देखने की बात है जिस से सरकार हरिजनों के साथ दे सके और हरिजन अपना अधिकार ले लें, उस में वह पिटें नहीं क्योंकि सरकार चाहती है कि हरिजन समस्या का हल हो जाय और अपने समाज में हरिजन और सवर्ण, अवर्ण, और सवर्ण नाम की कोई चीज न रह जाय, दोनों समाप्त हो कर एक समाज बन जाय । इस में हम कैसे उन की मदद कर सकते हैं इस के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा काम इन को मजबूत करने का सब से पहले है । यह जो सारी बातें होती हैं कि पुलिस में इन की भर्ती होनी चाहिये , प्रापर रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए, सर्विसेज में इन की भर्ती होनी चाहिए, इन को प्रापर रेप्रेजेन्टेशन देना चाहिए, और भी जो मांगें हैं अपनी जगह पर उचित हैं । लेकिन मैं दूसरी चीज की ओर संकेत करना चाहता हूं । सब से बड़ा प्रश्न आर्थिक है । इनकी कमजोरी उतनी फिजिकल नहीं है

जितनी कि आर्थिक है । एक तरफ बन्दूक है और दूसरी तरफ लाठी है —इस बात को भी मैं मानता हूं कि हरिजन लाठीधारी होते हैं और भूस्वामी बन्दूक धारी होते हैं उनकी लड़ाई बेमेल है । इसके बावजूद सब से बड़ा प्रश्न आर्थिक है । लाठीधारी भी बन्दूकधारी को पीट सकता है लेकिन असल कमजोरी यह है कि हरिजन के पास जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, उद्योग नहीं है, हरिजन के पास कोई असेटस नहीं हैं। इसकी वजह से वे कमजोर हो जाते है । वे संगठित भी नहीं हो सकते हैं। उन के पास हथियार भी नहीं है । लेकिन अभी मैं बात आर्थिक स्थिति की कर रहा हूं ।

सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है और इस बात का एलान किया कि पांच साल में अस्पृश्यता को खत्म करना है । यह जो कोढ़ है उसकी वजह से आज भी हम कमजोर बने हुए हैं और जब तक इस को खत्म नहीं किया जाता है तब तक हम कमजोर ही बने रहेंगे । इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने इस बात का एलान किया तो एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया ताकि वह कार्यक्रम सुझा सके । तो एक तरफ एलान हुआ और दूसरी तरफ कार्यक्रम बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया । केवल नीतियों के एलान से कुछ नहीं होगा, कार्यक्रम भी होना चाहिये जिस से कि पांच साल में इस कोढ़ से छुटकारा मिल सके। उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें बहुत सी अनुशंसायें हैं । मैं यहां पर केवल तीन का ही जिक्र करना चाहता हूं । एक अनुशंसा यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाये—यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज तक जितनी भी बातें हुई हैं तीस वर्षों में—मैं आलोचना के स्वर में नहीं कह रहा हूं—उस से यह बात स्पष्ट है कि जितनी भी योजनायें बनीं वह उन के जीवन को बिना छुए अगल-बगल से कतरा कर चली गई। यह आब्जर्वेशन मेरा नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन का है । यह जो विकास के काम हुए, निर्माण के काम हुए, योजनाबद्ध ढंग से योजनायें चलाई गईं उन से इस वर्ग के लोगों का कल्याण नहीं हुआ —यह स्पष्ट बात है । योजना बनाने वाले ही इस बात को कह रहे हैं । उस का फल यह हुआ कि हरिजनों को उसका लाभ नहीं मिला । फिर उनका विकास कैसे होता ? उनका विकास नहीं हुआ । इसलिए वर्किंग ग्रुप ने कहा कि योजनाओं की तहत लेकर इनका विकास करना होगा । पावर्टी लाइन से नीचे के जो 60 परसेंट लोग हैं उन में अधिकांश हरिजन ही हैं । जब तक आर्थिक रूप से इन को विकसित नहीं किया जाता है तब तक ये मजबूत नहीं हो पायेंगे । हमारा उद्देश्य यही है कि इनको हम मजबूत बनायें, संगठित बनायें, ताकि जीवन संघर्ष में वे जो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, जिस के कारण अत्याचार, जुल्मो सितम के शिकार होते हैं उस से उन को बचाया जा सके । इस के लिए उन का आर्थिक विकास होना जरूरी है । इस सम्बन्ध में वर्किंग ग्रुप ने तीन अनुशंसायें की हैं । एक तो यह कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाया जाये । क्योंकि हरिजनों का विकास मात्र होम मिनिस्ट्री का कन्सर्न रहेगा, मात्र राज्यों में वेलफेयर डिपार्टमेंट का कन्सर्न रहेगा ? इससे तो हरिजनों का विकास नहीं हो सकता । हरिजनों का विकास तभी हो सकता है जब कि जितने भी डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं चाहे वह राज्य सरकारों के हैं या चाहे केन्द्रीय सरकार के हैं, चाहे स्टेट प्लान में हैं और चाहे सेंट्रल प्लान में हैं जो भी डेवलपमेंट के सेक्टर हैं, उन सेक्टरों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान डालना होगा, उन में उन स्कीमों को आइडेंटीफाई करना होगा जो हरिजनों के जीवन को छुए, उनके जीवन का निर्माण करें और उनके जीवन का विकास करें। ऐसी स्कीमों को आइडेंटीफाई करना और जब ये आइडेंटीफाई हो जाएं, तो इन सेक्टरों के डिवीजिबिल स्कीम से इतना रुपया कम से कम ईयरमार्क करना होगा जितनी उनकी आबादी है । मैं बार बार यह कह रहा हूं कि उन की आबादी के अनुपात से होना चाहिए वैसे होना तो यह चाहिए कि गरीबों में जो उन की आबादी है, देश की कुल आबादी के 60 सैकड़ा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उन में भी 60 सैकड़ा लोग हरिजनों के हैं और उस अनुपात में रुपया दिया जाना चाहिये लेकिन कम से कम उन की आबादी के हिसाब से पैसा अलग कर दिया जाए और उन स्कीमों को आईडेंटीफाई किया जाए, जो उन के जीवन को बनाएं, इन के जीवन का निर्माण करें । इस तरह से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बना कर और हर सेक्टर में स्कीम बना कर के आइडेंटीफाई कर के डिवीजीबिल स्कीम से उतना पैसा ईयरमार्क कर के जितनी उन की आबादी है, उन के लिए काम किया जाए और फिर फैमिली के आधार पर या व्यक्ति के आधार पर स्कीम बना कर उस काम में उन को लगाना और टार्गेट्स निश्चित करना कि पांच साल में 50 सैकड़ा परिवार और 10 साल में 100 सैकड़ा परिवारों को हम छू लेंगे, तब जा कर उन के लिये काम हो सकेगा । इस लिए एक कमेटी बनादी है और उस से कहा है कि एक स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान बनाया जाए जैसे कि आदिवासियों के लिये सब-प्लान बना है तीन, चार वर्षों में यह सब-प्लान का विचार पूरा रूप ले चुका है । इस का एक

[श्री धनिक लाल मण्डल]

रूप बन चुका है, प्रकार बन चुका है, इस का एक रंग है और एक नाम है । जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उस में आदिवासियों के विकास के लिए हम एक सब-प्लान बनाते हैं लेकिन हरिजनों के साथ दिक्कत यह रही है कि हरिजन जनरल आबादी में घुले-मिले हैं।

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

उन से अलग नहीं हैं जैसे ट्राइबल हैं । वे एक खास कनसेन्ट्रेशन में एक जगह होते हैं । हरिजनों के साथ दुश्वारी यह है कि ये जनरल पापुलेशन में घुले-मले है और जनरल पापुलेशन को ऊंचा उठाने के लिए जो एरिया प्लान बनाते हैं, उस से इन को लाभ नहीं मिलता और जो मजबूत लोग हैं, वे लाभ उठा लेते हैं। ..... (**व्यवधान**) .... ठीक है, वे सब से गन्दी आबादी में बसते हैं, जहां पर शुद्ध हवा नहीं मिलती है । यह सब दिक्कत है । इसलिए मैं कह रहा था कि यह जो कहा गया कि से जनरल आबादी में आ जाते हैं, सभी के साथ आबादी में ये आ जाते हैं, तो इस में कोई दुश्वारी नहीं है । हम लोगों ने इस के लिये एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इस बात को देखेगा । जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ यही टार्गेट नहीं होना चाहिए बल्कि टार्गेट तो यह होना चाहिये कि उस इलाके में जहां हरिजन लोग घुले-मिले रूप में बसे हुए हैं, जनरल आबादी के साथ बसे हुए हैं और जब वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है , तो फिर उन को और ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए । इसलिए हम लोगों ने इस बात को स्वीकार कर के इस को अमल में लाने की कोशिश की है और मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हम लोग इस वर्ष सभी राज्य सरकारों से इस को मनवाने में सफल हो गये हैं । सभी राज्य सरकारों की राजधानियों में जा जा कर और उन के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर हम ने उन्हें सहमत करवाया कि इस साल जितने भी प्लान हैं, मिड-टर्म प्लान 1978-83 के, उन में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान डाले जाएं । उन्होंने ऐसा किया है चाहे अभी थोड़े रकम ही डाले गये हों । किसी किसी राज्य में 6 सैक्टर इयरमार्क किया है एलोकेशन और हमारा कहना यह है कि उन की आबादी के अनुसार होना चाहिये अभी एक शुरुआत हुई है , एक बिगनिंग हो गया है और विश्वास है कि जिस तरह से प्लानिंग कमीशन का आशीर्वाद इस को मिला हुआ है और भारत सरकार के प्रधान मंत्री का विश्वास इस को मिला हुआ है, इस में हम को विश्वास है, इस में हम को कोई हिचक नहीं है । यह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बढ़ते-बढ़ते सब-प्लान के मुकाबले में आ जाएगा जैसे कि ट्राइबल, आदिवासियों का सब-प्लान है उनके विकास के लिये सब प्लान है । इस स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को बढ़ा कर हम हरिजनों की तरक्की के लिये इसको मुख्य इंस्ट्रमेंट के रूप में व्यवहार करने जा रहे हैं । मैं इस बात को स्ट्रेस कर रहा था, तब कि जब हरिजनों की तरक्की के लिये कोई स्पेशल इंस्ट्रमेंट, मिकेनिजम को नहीं खोज लिया जाता तब तक जनरल प्लान से इनका फायदा नहीं होने वाला है । आज तक भी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होने वाला है । इसलिए इस इंस्ट्रमेंट को हम ने ढूंढ निकाला है और यह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हो सकता है । इसे हमने राज्यों में जा कर, राज्य सरकारों से बात करके बनाया है और हर सेक्टर में हम इसे डलवा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार के जो विभाग हैं उन से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि उनके जो डवलपमेंट सेक्टर हैं, उन में हरिजनों के विकास के लिए इस योजना के मुताबिक, स्पेशल कम्पोनेंट के मुताबिक काम करें और अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने विभाग में हरिजनों की स्कीमों को आइडेन्टीफाई करके हरिजनों की आबादी के अनुपात में रुपया इसमें रखा जाए। जो हरिजनों की आबादी है और उनके लिये जो टारगेट्स हैं उनको स्पष्ट, क्लीयर रखा जाए कि किस हद तक, किस पैमाने तक उन को उठाना है ।

मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि यह जो हमारा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का आइडिया है, जिस तरह का आदिवासियों के लिए सब-प्लान है, उसी पैटर्न पर हम इसका विकास कर रहे हैं और राज्य सरकारों से इसे स्वीकार कराने में हम सफल हो गये हैं । चाहे इस में अभी केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा थोड़े ही पैसे डाले गये हैं लेकिन यह पैसा बराबर बढ़ता जाएगा । जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह आन गोइंग प्लान की तरह है और एक साल से दूसरे साल में राशि एडजस्ट होती रहेगी ।

दूसरा इंस्ट्रमेंट भी हम फोर्ज कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ राज्यों ने शेड्यूल्ड कास्ट्स डवलपमेंट कारपोरेशन बनाये थे । खास कर के दक्षिण के राज्यों ने बनाये थे । पंजाब और हरियाणा में भी बने थे लेकिन वहां इनका बहुत अच्छा काम नहीं हुआ । मैं जो शेड्यूल्ड कास्ट्स कारपोरेशन हैं, इनका वित्तीय आधार कमजोर है और इनमें फाइनेंशयल ईस्टीट्यूशंस से भी कम पैसा आता है , इसलिए इनको बढ़ाने के लिये इन में केन्द्र का भी पार्टिसिपेशन मंजूर करवाया है । इस साल जो कि बीत गया है, उस में 50 लाख रुपया रखा गया था लेकिन इस साल दस करोड़ रुपये है की मंजूरी दी है । राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन बने हुए हैं उन में शेयर कैपिटल में केन्द्रीय सरकार की हिस्सेदारी 49 परसेंट की होगी और 51

परसेंट राज्य सरकार लगायेंगी । इस आधार पर अब और राज्यों में भी यह काम शुरू हो गया है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि इस साल चार स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कारपोरेशन बनाये हैं और इन में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य भी सम्मिलित हैं जहां सब से अधिक हरिजनों के विकास की समस्या है । जहां केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से यह बात की है कि वह भी इस में शामिल होना चाहती है वहां उन्होंने भी अपने अपने डैवलपमेंट कारपोरेशन बनाये हैं ।

इसका उद्देश्य यही , क हम इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हरिजनों की सेवा करना चाहते हैं । हरिजनों के लिए जो इस बारे में हमने नियम बनाये हैं वे ये हैं कि एक-एक स्कीम अधिक से अधिक पांच हजार रुपये की होगी, उस से अधिक की नहीं होगी जिससे कि अधिक से अधिक हम उन को ऊंचा उठा सकें । एक का मैं ने उदाहरण दिया । ऐसे बहुत से राज्य हैं सब का मुझे याद नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि जो वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की है हमको स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस भी चाहिये हरिजनों के काम को उनके विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिये, तो इस पर हमारा प्रयास हो रहा है, क्योंकि जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक राज्यों को प्रोत्साहन नहीं होगा । मैं एक जानकारी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं यद्यपि उन्होंने बहुत से प्रश्न उठाये हैं, माननीय राम विलास पासवान यहां नहीं हैं जिन्होंने हरिजन ऐट्रोसिटीज के बारे में प्रश्न उठाये, लेकिन मैं ने आपको बताया कि जो मुख्य बात है वह यह कि हमारा ध्यान इनके आर्थिक विकास की ओर होना चाहिये जहां से मजबूरियां पैदा होती हैं, जहां से बान्डेड लेबर पैदा होते हैं । इसको दूर करने के लिये हमारा प्रयास होना चाहिये । और उसके लिये जो हमें इन्स्ट्रूमेंट बनाने चाहियें, स्पेशल प्रोसीजर या मेकेनिज्म तैयार करनी चाहिये जिससे उन तक लाभ पहुंचा सकें, विकास का काम पहुंचा सकें, इस काम को ठीक करने के लिये हम जाग्रत हैं । इसलिये यह कहना कि राष्ट्रीय ताने बाने को और देश के अन्दर इसको सुदृढ़ करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है मैं, समझता हूं कि यह आरोप निराधार है । बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि जितना पहले कभी नहीं ध्यान दिया गया, उससे ज्यादा ध्यान इस ओर दे रहे हैं ताकि पांच साल के अन्दर सरकार के संकल्प के अनुसार हरिजन सवाल हल हो जाय । मैं इसको मिनिमाइज नहीं करता हूं मैं जानता हूं कि काम बहुत बड़ा है, समस्या बड़ी विकराल और जटिल है, लेकिन हमारा संकल्प भी उतना ही महान है और हमने प्रयास आरम्भ कर दिया है सही दिशा में । और मेरा विश्वास है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाते जायेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस समस्या को हल करेंगे ।

श्री ...लाल : मंत्री जी क्या बतायेंगे कि जो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन्स हैं और जिन पर हमारा अरबों रुपया खर्च हो रहा है वहां के लिये आपने क्या किया है ? वहां भी उनको कोई रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं ?

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister will reply later on.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Mr. Chairman, Sir, even after hearing the speech of the State Minister, my view is that the Home Ministry has not yet been seized with the problems facing them. I need not emphasise that this is the most important Ministry, the effective functioning of which will ensure the health of the nation. Unfortunately, they do not discharge their duties for various reasons and the Ministry stands paralysed. As he himself pointed out, it is not because of administrative reasons. The basic reason is the inherent conflict between the character of our State which is democratic and secular and the political philosophy of Hindu Rashtra which runs counter to it. That philosophy has now gained a place in the ruling circles. That has created an entirely different situation in the country. I am not suggesting that any of the Ministers concerned coming from the Jan Sangh Party is instigating anyone. But their mere presence in the Ministry unleashes the anti-democratic and anti-secular forces in the country and it is they who are creating the problems which, it is very difficult for you to handle. Since you have entered into a fraternity with these forces and so your hands are tied. That is the basic problem.

As long as such a political philosophy is in the ruling group, however

[Shri M. N. Govindan Nair]

much you may try—I do not say that you have not tried it—with sincerity, Mr. Mandal, the situation will only aggravate. Here what Gandhiji said immediately after Partition becomes very pertinent. He pleaded with the entire nation that India is not a land only of the Hindus but a land of Muslims, Christians, Shik, Parsis etc. Everyone who is loyal to the Indian Union should have the full rights in this country. We have adopted the principle in our Constitution. This comes into direct conflict with the idea of Hindu Rashtra where they may tolerate other communities and other religious groups if they behave. So, the solution: You have the majority. If you want you can reorganise the Government without such elements and find a happy solution.

Now, because of this kind of development, the Muslims, the Christians and everybody is feeling insecure. I need not repeat what happened in Aligarh and all that. There is a general feeling, there is a fear among the Muslim community that they are not treated as normal citizens; they are treated as second class citizens. The same fear is among the other sections also. Now the Christians have that fear because, in the name of Freedom of Religion, you are trying to restrict their activities.

Look at the whole picture. Excepting Hindus, that too, upper-class Hindus, who will remain safe in this country? Hindus are not a homogenous community—there are the tribals; there are the backward clases. Are you prepared to accept their rights as equal citizens of this country? In theory you do but, in practice, you deny. That is the problem. Unless you are able to solve this political problem, however sincerely you may wish or however sincerely Mr. Mandal may wish, you will only be in a soup, you are in a soup. I do not want to go into further details.

The second point is about police. They are guided by the Police Act 1861. Their approach is the same as during the British times. Have you tried to bring about any change? You have appointed a National Police Commission but they are not going to look into these problems. A police machinery built up not to help the people but to suppress the people. If they feel their job is to harass the people how can you utilise such a machinery for the betterment of the administration? It is not only that the approach continued but also after Independence they are becoming a tool in the hands of the ruling political parties. Who rules is not the question. They have been taught to behave in that way. Are you thinking of any change? You are not. When you were in the Opposition you felt so but now when you are in the Administration you want them to behave the same way as they behaved earlier. This must go. In Britain the police is not under the control of the executive. It is only the Parliament that can appoint the Chief Police Commissioner and also it is only he who can give orders to the department. Here it is not only the Minister but also anybody belonging to his political party can go to the police station and demand of them to behave in a particular way. I would not like to suggest that you should follow either the U.K. or the USA system but I would like to give the example of Japan. In Japan it is a public safety commission consisting of the representatives of all the political parties that controls the police administration. They formulate policies. They review their activities. Why can't you bring forward such a change. Even in the political complexion of your government remains as defective as I pointed out earlier, if the police is brought under a better control—as has been suggested by me, many of the evils can be avoided. Are you prepared to do it?

Then another very important matter is that you must immediately dis-

band your intelligence wing of the police department. I do not know why they waited upto this day to do that. Whichever that government be the intelligence wing in the eye of the government. No minister can go round and find out what is happening. They must observe scrupulous objectivity in reporting and unless the government is aided by such a machinery they will find it difficult to arrive at correct decisions. I am not saying that the Intelligence Wing is not necessary: it is necessary but what is your Intelligence? The whole country was humilated before the entire world the other day when the Intelligence Department reported to the Prime Minister that J. P. Narayan was dead. Fortunately he is alive even today, Sir. How could it happen? I am not blaming the Prime Minister for making a wrong statement. But I can never understand how after that incident the same Director or the same Commissioner is sitting there in their respective chairs. You say you are instituting an enquiry. What enquiry? They must be dismissed; they must be disbanded. The whole wing should have been reorganised by this time. It is not only a question of wrong reporting about JP's death. If this is the casual way in which the Intelligence Department does its work, what is the use of having these people there? You should reorganise the whole department and you should bring in some new people who have a full sense of objectivity.

Then, Sir, I would request not only Janata Ministers, but Janata Members to refrain from bringing in legislation which will undermine democracy and secularism in this country. I am referring to the Freedom of Religion Bill brought forward by Shri O. P. Tyagi. What is the objective of this Bill? It is only for restricting the activities of the Christian Missionaries. I want a special commission to go from your Department to Mizoram. Let them study what has happened in Mizoram in the field of socio economic development, and what is the state of affairs there now. You go to Bastar, a nearby place. It is a tribal belt. But look at their tragic conditions. In Mizoram, the Christian Missionaries have educated them, raised their political level, raised their social level and cultural level. If you go there, you will feel you are in a modern town. Has it any comparison with Bastar? In such a situation, why should you come forward with such Bill? I am not for conversion of people by inducement and so on. That is not my idea. There is another Bill regarding ban of killing of cows and bulls. Already there is confusion in the minds of the minorities and other sections. There are many people in the country who eat meat, among Hindus, among scheduled castes, scheduled tribes, backward classes and others. All of them use meat. And now another private Member is bringing a Bill to ban the slaughter of bulls and calves. Bulls should not be killed. You know what has happened to Jethmalani's Bill. He brought his Private Member's Bill. But that has been pocketed by the Government. The other day this Religious Freedom Bill has been brought in by the private member. The Prime Minister, without even discussing it in the House, has blessed this Bill. Who knows, tomorrow Mr. Patel may say, killing of calves and bulls must be stopped? This kind of approach without respecting the sentiments of all the people of this country is not correct. India is not a land of the caste Hindus alone. India is a land of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Muslims Christians, Sikhs and so on. So, if you don't have that feeling if you don't have that respect, for all the communities residing in this country, you will only be leading the country to disaster. Thank you.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tezpur): Sir, I heard the speech of my hon. friend, Mr. Govindan Nair. If I were on that side, I would have rightly supported him in demanding the immediate removal of those offi-

[Shri Purnanarayan Sinha]

cers who had given false information and thus putting the Prime Minister and the House into disrepute. They have failed everywhere and in 1962 our military intelligence also failed. There was catastrophe in the North-Eastern frontiers during the Chinese aggression. They had failed in informing the Government during the aggression.

And now, in our country, there are people among the tribals who are still naked. Recently I put a question as to whether the Government was aware that there were people who were traditionally naked in India even today. The Intelligence of the Indian Police Service have failed to collect truth of this information. But we have seen them with open breasts, hardly covering their body. They are in Koraput District, that is, in the Bonda Hills in Orissa. In these hills they openly live naked. But the Police have never seen them in those open areas and they could not report to the Government. I have received a reply from the Minister that there was no information about this. But some of us have seen them. Is it not a matter of shame? Yes, it is a matter of great shame, since the Home Ministry is looking after the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The hon. Minister is advocating many things and he is in sympathy with the scheduled castes but he has carefully avoided to say anything regarding Scheduled Tribes. But there are regions, there are States in India where the Scheduled Tribes form a majority of population.

Now, in this report, on which this discussion is based, there is a mention about the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in various States. Out of the total population of 51,25,00,000 in 1971, about 4 crores are scheduled tribes. For the development of the Scheduled Tribe regions for the benefit of the Scheduled Tribes, there are many schemes planned over the last 30 years of our republic and one such was the Dandakaranya projects. The Government has spent till date an amount of Rs. 102.0 crores in the Dandakaranya projects. Recently, a parliamentary team went there to see the progress of various projects, to have an indepth study. We were taken here and there by the local officials to show us the progress made in the area. But things have been done in such a way that in one place, that is, Dandavada, in Madhya Pradesh, where a lift irrigation canal has been dug to take the water from the reservoir, the water does not flow from the reservoir but on the contrary the water flows back to the reservoir. It is axiomatic that water would always flow from higher level to the lower level. But here it is happening quite the opposite. We saw it with our own eyes and we also pointed out this to the officials. They were trying to side with the Engineer who constructed the reservoir about 1-1/2 years ago. They have spent about Rs. 4.5 lakhs in constructing this reservoir and canal. This is how the developmental activities are taking place in the tribal areas of this country where people are still naked. They are pampered by the American tourists by a ten-rupee note and they take the photographs of these people and publish them in their 'Playboy' magazine. In this way, certain development projects have been taken up in tribal sub-plan areas. But with what heart? Has it been done whole-heartedly to do good to the tribals? No; it has been done half-heartedly.

Sir, there is a national highway in the tribal region of Dandakaranya in Madhya Pradesh where 99.98 lakhs, about one crore people, are tribals. You will find there women wearing very little on their waist line, having completely bare breasts and carrying head-loads and sling loads across their shoulders walking along with men on that national highway. What has been done to remove their poverty, to

save them from this nakedness? They have been living like this. They live in jungles and among savage animals, but are surrounded by civilization and States like Madras, UP and Bihar. They have been allowed to live like this. In my region, the tribals are in a majority. If Assam were not divided to give the tribal people their own rule, Assam would have been today like Madhya Pradesh which has the largest number of scheduled tribes.

As we know, the people in these areas are in the habit of shifting cultivation which is the main cause of their poverty. This has not been removed. In the tribal sub-plans, the first thing which was due to be done was converting their system of cultivation from this to terrace cultivation. That has not been introduced. They could not be brought to the developed ways of cultivation.

In this report, on page 98, under 'Research and Policy Division,' it is mentioned and the hon. Members may see it for themselves:

> "The Research and Policy Division has assigned a study on 'Insurgency in North-East' to the Institute for Defence, Studies and Analyses, New Delhi."

This is the single sentence mentioned in para 3.1 here. I do not see any head or tail of this. What is the purpose of such an investigation? Will the result of this investigation see the light of the day and whether it will be placed on the Table of the House and we will be able to read and learn something out of it, I do not know. But then this is something done half-heartedly concerning scheduled tribes.

Now, I come to the recruitment policy as far as police is concerned. The recruitment of people in the I.P.S. is quite opposed to the way the British used to recruit from the post of Sub-Inspectors onwards to IPS officers during their domination in our country. Today people are recruited to this department from such categories, that strata of society, who have no other job and they come to take up the police job. When you do not find any other respectable job, you become a constable. People who are outcast and are unwanted anywhere else, come to the police department and they make the ideal police. Persons recruited from such classes do not make ideal policemen. They go there just for money and power. Power begets money. Even a police constable after retirement is much happier man than an honest I.A.S. officer. This is happening and even today that character has not changed. During the eleven years' rule that we had, the persons who were recruited to the police department, were perhaps from the worst classes and as a result, today the Harijans are the victims of many atrocities. Tribals are being ignored. Other people are also not getting jobs. You have created the police all right. Every State has to have Police, but when starting a police station—or in the existing police stations—have you, till to-day either from the Centre or from the States, been able to connect the police stations by wireless? Or, have you given a jeep to every police station, to make them more mobile, so that on getting information about an intended dacoity, burglary or any other crime which is likely to result in loss of lives, they can offer assistance to the people, in order to save the lives of the people?

We have urged in this House last year that Police must be made more mobile. They should be given equipment, and police stations should be connected by wireless, so that we can at least demand some efficiency from the Police, something more than what they have to-day.

I am sorry to note that in this Report, there is no indication that the Union Government will go to assist the State Governments and make the Police more mobile and more useful to the society.

[Shri Purnanarayan Sinha]

I now come to the North-East. Jharkhand, in Bihar, has not been created as a separate State, in order to give a special ethnic status to the Munda, Oraon and other Adivasis. The same thing should have been applied to the undivided north-eastern region; and separate states should not have been created for 3 or 4 lakhs of people. But now, separate States have been created there. Whatever may be the purpose for which they were created, has the Home Ministry been able to keep them together like a joint family of people living in the plains or hills? There are border conflicts there, between different States. Why? You have created the States. Was it not your business to demarcate the boundary lines? You divide the property between your two sons; they will fight for their shares unless you divide the property by a pillared demarcation. They fight. There are skirmishes along the Assam-Nagaland border as also on the Assam-Meghalaya and Assam-Arunachal borders. You said the State Governments will look after these incidents, or that the Chief Ministers will sit down together and sort out the matters. It is an impractical thing. It is the business of the Union Home Ministry to demarcate the boundary lines and bring peace to that area.

In Nagaland, Naga people are there. But Naga people are there in Assam also. There is a Naga mouzadar in Assam, and he is collecting revenue near Lumding, which is very much Assam territory.

Then comes the question of Indo-Bangladesh border. The demographic character of Assam is being changed. In about 10 or 20 years, I as an Assamese will have no place in my State. We will die out, or be wiped out. Our identity will be obliterated by the onrush of people from other areas, particularly Bangladesh. The Home Ministry has totally failed to check the inroads by the infiltration of foreigners into India. I do not discriminate between Bengalis and Assamese and say that the Bengal culture is infiltrating. I do not say that the Muslims are infiltrating. I say they are foreigners, for all practical purposes.

I demand of the Home Ministry: if you cannot control the Indo-Bangladesh border and cannot check infiltrators from that country coming to India and creating law and order and security problems for the States, please make it the responsibility of the Indian Army.

Let the para military forces assist our army in checking infiltration of foreigners into India. This is my demand and I want that this demand should be accepted in order to save our borders, in order to maintain our national identity, as people of the north-east region. You will have to do some thing which will be changing the political picture of India in the north-east region to a great extent. With these words, I conclude my speech.

श्री के. एस. नारायण (रदरावाद) : मैं ने बहुत ही श्रद्धा से और ध्यान से गृह राज्य मंत्री श्री छनिक लाल मंडल का भाषण सुना है। उन्होंने शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। मैं आशाकर रहा था कि एक आध लफ्ज वह सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासिस के बारे में भी शायद कहेंगे लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी उनके बारे में नहीं कहा। इस का मुझे बहुत अफसोस और दुख है। उन्होंने इतना ही कहा कि एक बैकवर्ड क्लासिस कमिशन हम लोगों ने बनाया है और दो मकसदों को सामने रख कर बनाया है। पहला तो यह है कि इस के लिए क्राइटीरिया क्या हो इसको वह बताए और दूसरी बात यह बताए कि क्या क्या उनके लिए डिवेलेपमेंटल प्रोग्राम हाथ में लिए जा सकते हैं और वह तजवीजें पेश करे इनक्यूडिंग रिजर्वेशन। इसके सिवा उन्होंने कुछ भी उनके बारे में नहीं कहा है।

मैं जिन के बारे में बोल रहा हूं उनकी आबादी इस मुल्क के गरीब लोगों में पचास परसेंट से भी ज्यादा से भी ज्यादा है जो बैकवर्ड क्लासिस कहलाते हैं जो पचास परसेंट से भी ज्यादा हैं। कई जगह तो उनकी हालत हरिजनों से भी बदतर है, यह मैं अपने परसनल नालेज के आधार पर कह सकता हूं। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को कास्टीट्यूशनल सेफगार्डज मिली हुई हैं, लीगल सेफगार्डज उनके लिए हैं और उनके लिए बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने

... भी है, यह मैं मानता हूं । जो किया गया है वह कम है इसको भी मैं मानता हूं । लेकिन बैकवर्ड क्लासिस के जो लोग हैं खास कर उनके जो एज ग्रोल्ड प्रोफेशन हैं, जैसे वीवर्ज़ हैं, टैपर्ज़ हैं, पाटर्ज़ हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, कारपेंटर्ज़ हैं, बारबर हैं, वाशरमैन हैं या इस किस्म के ग्रौर भी जो लोग हैं, उनके वास्ते कुछ भी नहीं किया गया है ग्रौर किया गया है तो बहुत कम किया गया है । 31 साल की ग्राजादी के बाद ग्रौर प्लांड डिवेलपमेंट के बाद भी कई जगह उनकी हालत बद से बदतर हो गई है । उनके बारे में न तो पुरानी हकूमत ने उतनी तवज्जह दी ग्रौर न ही ग्राज की हकूमत दे रही है । यह भी वही गलती कर रही है जो पुरानी हकूमत ने की थी, इसका मुझे खेद है । कई स्टेट्स में उनके वास्ते प्रोग्राम्ज़ बनाए गए हैं लेकिन सैंटर की तरफ से कुछ भी उनके बारे में नहीं किया गया है । फिफटीज़ ग्रौर ग्रर्ली सिक्सटीज़ में पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कालरशिप्स कुछ लोगों को दिए गए थे कुछ स्टेट्स में लेकिन उनको भी बन्द कर दिया गया है, 1962 के बाद से उनको ये भी नसीब नहीं हैं । ग्रग्रणी श्रेणियों के जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करने को ग्रगर इनको कहा जाता है तो कैसे हम इनके साथ इंसाफ कर सकते हैं । मैं ग्रांध्र से ग्राता हूं । ग्रांध्र ग्रौर कर्नाटक की बात मैं जानता हूं । वहां उनके बारे में कुछ करने की कोशिश की गई । इसको लेकर कोर्टस् में बहुत दिनों तक लिटिगेशन चलता रहा, साल दो साल तक चलता रहा । कुछ रिजर्वेशन उनको सर्विस में ग्रौर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंज़ में दी गई हैं । बैकवर्ड क्लासिस फाइनेंशियल कारपोरेशन भी हमारे यहां बना है ताकि जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनकी कुछ मदद की जा सके । लेकिन स्टेट गवर्नमेंटस के पास रिसोर्सिस बहुत कम हैं ग्रौर जब तक सेंटर बड़े पैमाने पर, इन ए बिग वे उनकी मदद नहीं करेगा यह काम ग्रागे बढ़ने वाला नहीं है । ग्रौर मुझे डर है, मैं सरकार को वार्निंग देना चाहता हूं कि जो ग्रापने कमीशन को कहा है कि सोशली ग्रौर एजूकेशनली बैकवर्ड क्लासेज़ कौन हैं इसको रीडिफाइन करें क्राइटीरिया बनाये यह उचित नहीं है । काका कालेलकर की रिपोर्ट ग्रापके पास है उसके ग्राधार पर ग्राप क्राइटीरिया तय कर सकते हैं । ग्रान्ध्र प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन बना है ग्रौर कुछ लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गये, 1972 की जनवरी में जजमेंट हुग्रा ग्रौर जो क्राइटीरिया ग्रान्ध्र प्रदेश ने फिक्स किया है उसको मान लिया गया है । जब सुप्रीम कोर्ट ने, उस क्राइटीरिया को मान लिया है फिर दूसरे कमीशन बैठा कर ग्राप दूसरा क्राइटीरिया क्यों मांग रहे हैं ? इससे काफ़ी लीगल कामप्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे । इसलिये मेरी दर्खास्त है कि ग्राप इस बात में न जाइये । सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है, कर्नाटक का मुझे मालूम है वहां माना जा रहा है, ग्रब बिहार में उसका इमप्लीमेंटेशन हो रहा है । जहां नहीं हुग्रा है वहां पर ग्राप काम शुरू कराइये ग्रौर उनको मदद देने की कोशिश कीजिये । न कि दूसरा कमीशन बैठा कर रिपोर्ट लें ग्रौर देर करें । ऐसा करने से झगड़े पैदा होंगे ग्रौर देरी होगी । सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के बारे में है उसको ग्राप मान लीजिये ग्रौर उसी बुनियाद पर इस काम को ग्रागे बढ़ाइये ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को फ़ाइनेंशियल ग्रसिस्टेंस बहुत बड़े पैमाने पर देनी चाहिये क्योंकि 50, 60 फ़ीसदी इनकी ग्राबादी है । इनका ग्रगर कल्याण होगा तो देश के बहुत बड़े हिस्से का कल्याण होगा । इसलिये इतने बड़े नगलेक्टेड सेक्शन को, ग्रौर खासकर देहातों में जो उनकी बहुत खराब हालत है, उनकी बेहतरी की तरफ ग्रापको ज्यादा ध्यान देना चाहिये । जो स्टेट फ़ाइनेंशियल कौरपोरेशन्स हैं उनसे मदद दिलाइये, जहां बकवर्ड क्लासेज़ कमीशन नहीं है, वहां बनाइये ग्रौर स्टेट तथा सेन्ट्रल सर्विसेज़ में उनका रिज़र्वेशन कराइये । यह कोई मेहरबानी की बात नहीं है । जिस तरह ग्राप शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर ट्राइब्स को रिज़र्वेशन दे रहे हैं वैसे ही बैकवर्ड क्लासेज़ के बच्चों को भी 10, 20 साल तक रिज़र्वेशन दीजिये ताकि वह भी दूसरे लोगों के मुकाबले में सोसायटी में ग्रागे ग्रा सकें । ऐसी मेरी मांग है । स्वीपर ग्रादि के बच्चों के लिये सरकार ने जो स्कालरशिप प्रोवाइड की है, यह बड़ी ग्रच्छी बात है ग्रौर इसके लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं । ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेज़ के बच्चों के लिय भी करना चाहिये । जनता पार्टी की ग्रगर ग्राज सरकार है तो इन्हीं लोगों की मदद से ग्रापकी पार्टी है ग्रौर ग्राप हुकूमत में हैं । उनको मदद करना ग्रापका फ़र्ज है ।

शैड्यूल्ड कास्टस ग्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो रिज़र्वेशन्स हैं उनके इमप्लीमेंटेशन में कमी है, ईमानदारी से इमप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है । इस ग्रोर ग्रापको ध्यान देना चाहिये । ग्रभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि कुछ सैल बना रहे हैं, ग्रौर जो रिज़र्वेशन है शैड्यूल्ड कास्टस ग्रौर ट्राइब्स के लिये वह जनवरी में खत्म होने वाला है । मैं मांग करता हूं कि 10 साल के लिये उसको ग्रौर बढ़ाना चाहिये ।

पेंशन टू फ्रीडम फ़ाइटर्स के बारे में मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि जो 200 रु० की पेंशन उनको दी जा रही है वह बहुत नाकाफ़ी है । ग्राजकल के महंगाई के जमाने में उनको मान्यता दे रहे हैं । 25 साल तक फ्रीडम-फाइटरों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, 25 साल की ग्राजादी के बाद उनके बारे में सोचा गया । उसके बाद शायद ग्राधे लोग मर चुके हैं । बहुतों के मरने के बाद यह काम किया गया । मेरा कहना है कि इनको कम-से-कम 500 रुपये पेंशन देना चाहिये, 200 रुपये बहुत कम है ।

उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है कि ग्रगर फैमिली में कोई 500 रुपये की ग्रामदनी है तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी, यह ठीक नहीं है । 500 रुपये तो ग्रगर

[श्री के० एस० नारायण]

उसकी बीबी या बच्चा कोई नौकरी करता है, तो उसको मिल जाता है और इस तरह से वह 500 रुपये की पेंशन से महरूम रह जाता है। मेरा निवेदन है कि इस रिस्ट्रिक्शन को आप निकाल दीजिये। जो 6 महीने के लिये जेल चला गया, उसको आप पेंशन दे रहे हैं लेकिन जो 5 महीना 29 दिन जेल में रहा उसको देने से इनकार कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये। सब को पेंशन देना चाहिये। अगर इसमें 25, 50 करोड़ रुपया देना भी पड़ता है तो देना चाहिये। इन लोगों ने मुल्क के लिये बिना किसी इन्ट्रेस्ट के कुर्बानी दी और आगे आये। इनके लिये आप आगे-पीछे कुछ मत कीजिये, सब रिस्ट्रिक्शन को निकाल दीजिये। दिल खोलकर इन लोगों को दीजिये।

मैं माइनौरिटीज के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं हैदराबाद से आता हूं, वहां मुस्लिम पापूलेशन बहुत ज्यादा है। उन लोगों के लिये आपने कमिश्नर बैठाया है। वह कमिश्नर किस ढंग से काम कर रहा है, वह तसल्लीबख्श नहीं है। उसके काम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। उन लोगों के दिल में दहशत है। जो रायट्स अलीगढ़ या दूसरी नगरों में हुए हैं, आप आंकड़े देख सकते हैं, कांग्रेस के जमाने में ज्यादा हुए या आपके जमाने में। मैं चाहता हूं कि उनमें कान्फीडेंस पदा करने के लिये कोई व्यवस्था हो। आप उनके मुस्लिम पर्सनल-ला को टच मत कीजिये। जिस तरह से क्रिश्चियनों के बारे में आपने किया है उसी तरह से मुसलमानों में माइनौरिटीज में भी क्लाइमेंट आफ कांफ़ीडेंस पैदा करने की जरूरत है।

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा (चतरा) : सभापति महोदय, अभी सदन में गृह-मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चल रही है। यह महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें कोई दो राय न''ीं हैं। सिर्फ इसलिये नहीं कि यह विभाग सामान्य प्रशासन, कानून और व्यवस्था को बनाये रखता है, बल्कि मैं इसलिये इसे महत्वपूर्ण विभाग मानता हूं कि इस विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि यह जो अविकसित देश है, यहां के लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं, यह उनको विकसित करे। देश पर जो पिछड़ेपन का कलंक है, इसे मिटाने की भी जिम्मेदारी बहुत अंशों में इसी विभाग के ऊपर है।

मैं बहुत गौर से माननीय गृह-मंत्री श्री धनिक लाल मंडल का भाषण सुन रहा था। बातें वह ठीक कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि जब से जनता सरकार आई है, वह चिन्तित है और कार्यक्रम बना रही है, लेकिन एक बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप चाहे जितने भी कार्यक्रम बनायें, जितनी भी उनके विकास की योजनाएं बनायें, उनकी गरीबी और बेकारी को दूर करने के सम्बन्ध में योजनाएं बनायें, लेकिन यह न भूल जायें कि पहले से लेकर अब तक इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी किस पर है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि आपकी नौकरशाही, जिनके जिम्मे कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है, वह ईमानदारी के साथ आपकी योजनाओं को, जो कमजोर वर्गों, आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आप करना चाहते हैं, क्या वह दिल से करना चाहते हैं?

15 hrs.

मंत्री महोदय के पास सारे आंकड़े हैं। हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन तो बहुत पहले से है। वह देखें कि इन वर्गों के लिए जितने स्थान सुरक्षित हैं, क्या वे सब भरे जाते हैं। वह कहेंगे कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लायक भी नहीं हैं, क्या वे पियुन और चपरासी का काम भी नहीं कर सकते हैं। हरिजन और आदिवासी भूखों मर रहे हैं, लेकिन वे पियुन और चपरासी भी बहाल नहीं हो सकते हैं। इन पदों पर भी सवर्ण परिवारों के लोग आते हैं, जो भूस्वामी भी हैं। उनमें से जो पढ़े-लिखे हैं, वे तो बाबू और अफ़सर बन जाते हैं और जो पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, व चपरासी बन जाते हैं। मंत्री महोदय पर सब से बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह नौकरशाही के हृदय को कैसे बदल सकते हैं, या कैसे उस पर अंकुश लगा सकते हैं।

अगर मंत्री महोदय इस बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उनकी सब योजनायें धरी की धरी रह जायेंगी, और जिस तरह हमारी फ़ाइव-यीअर प्लान्ज का लाभ देश के साधारण लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, उसी तरह इन योजनाओं का लाभ भी हरिजनों और आदिवासियों तक नहीं पहुंचेगा, और इन का लाभ उन्हीं वर्गों के लोग उठायेंगे, जिनकी शरण में रह कर हरिजन, आदिवासी और ग़रीब लोग अपना जीवन बिताते आ रहे हैं।

ये योजनायें हरिजनों और आदिवासियों तक कैसे पहुंचें? मंत्री महोदय स्वयं नहीं पहुंचा सकते हैं और हम भी नहीं पहुंचा सकते हैं। हां, हम लोग हल्ला जरूर कर सकते हैं और करेंगे। इन योजनाओं का कार्यान्वयन तो अधिकारी करेंगे। आज परिस्थिति यह है कि प्रशासनिक यंत्र को जंग लग गया है, वह शिथिल हो गया है, और हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति उसका ईमान भी सही नहीं रह गया है। वे लोग यह नहीं चाहते हैं कि इन वर्गों का विकास हो। इस का परिणाम यह है कि हमारा देश दुनिया में बहुत पिछड़ा हुआ है। और यहां पर 60 प्रतिशत लोग ग़रीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। सरकार को यह भी विचार करना चाहिए कि देश में पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले 60 से 80 प्रतिशत लोग कौन हैं—वे हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं।

इस प्रश्न पर बड़े जोर-शोर से चर्चा होती है कि किसी को आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा माना जाये या सामाजिक दृष्टिकोण से। मैं इस प्रश्न का जवाब

मंत्री महोदय से चाहता हूं । कहा जाता है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन के कारण देश में अत्याचार होता है, लोगों को दबाया और सताया जाता है, तो सवर्णों लोग भी सताये जाते । लेकिन यह बात नहीं है । सताये वही लोग जाते हैं, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इस लिए अत्याचार हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर होते हैं । इसलिए यह निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि जो लोग आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, उन्हीं के कारण देश कमजोर हो रहा है । जब तक उनका विकास नहीं होगा, तब तक देश सबल नहीं होगा, यह बात निर्विवाद है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हरिजन गांव के दक्खिन में बसता है । श्री मण्डल बिहार से आते हैं और मैं भी बिहार से आता हूं । आप बिहार के ऐसे किसी गांव भी में जायें, जहां सवर्ण लोग तथा हरिजन और पिछड़े लोग रहते हैं । अगर आप किसी से पूछें कि किसी हरिजन, या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के किसी आदमी का घर किस तरफ़ है, तो जवाब मिलेगा कि इधर तो स्वर्ण लोग रहते हैं, राड़—नीच—लोग अलग रहते हैं, दूसरी तरफ रहते हैं ।

15.06 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

आज यह सब से बड़ा सबूत है कि 30 साल के बाद भी नीच और राड़ शब्द गांवों में उन वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें आप कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, पावर्टी लाइन के नीचे हैं । उन का सम्बोधन नीच और राड़ के साथ किया जा सकता है इस से बड़ा प्रमाण और क्या मिल सकता है ? अगर लोग चाहें, मैं धनिक लाल मंडल जी के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो हमारे साथ रहते ही हैं, वह भी बिहार के ही हैं, वह जानते हैं लेकिन दूसरे लोग अगर चाहें तो उन को मैं निमंत्रण दूंगा, वह हमारे साथ चलें, मैं उन को उन गांवों में भेजवा दूंगा, वहां जा कर वह पूछें, मैं, नाम बता दूंगा, हरिजन का और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का, उन के बारे में पूछें तो वह कहेंगे कि राड़ लोग उधर रहते हैं । तो यह जो समाज की बनावट है इस को मिटाने के लिए जरूरत किस बात की है ? सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ऐसे लोगों को आपको लाना होगा । कैसे ला सकते हैं ? आज यह बात सही है कि सारी नौकरियों में उनको जगह दे कर सब का आर्थिक विकास आप नहीं कर सकते हैं लेकिन सम्मान कर सकते हैं । आज एक हरिजन, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कोई अधिकारी बन जाता है तो उस के सामने लोग उस की प्रतिष्ठा करते हैं । आर्थिक दृष्टिकोण से भी वह सबल होता है लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उसको प्रतिष्ठा मिलती है और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज इस देश में सामाजिक अव्यवस्था और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए आप सर्विसेज में चाहे वह राज्य की सर्विस हो या केन्द्र की हो, पिछड़े वर्ग के लोगों को, हरिजनों को और आदिवासियों को रिजर्वेशन दें । अगर आप नहीं देते हैं तो सचमुच में आप की नीयत साफ नहीं समझी जायगी क्योंकि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए उन को सम्मान देना जरूरी है । आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए भी देना चाहिए । आज क्यों ऐसा हुआ कि सर्विसेज में उनकी संख्या इतनी कम है ? प्वाइंटिंग अथारिटी कौन है ? नियुक्ति करने वाले कौन हैं ? वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सदियों से पिछड़े हुए, गरीब और सताए हुए लोग आगे न बढ़ने पाएं । बिहार तो जातीयता के लिए बहुत बदनाम है, वहां तो ऐसी स्थिति है कि ऐसी जाति के लोग वहां अधिकारी हैं कि चतुर्थ वर्ग से लेकर ऊपर तक की जितनी नियुक्तियां होती हैं वह सब जाति के आधार पर होती हैं, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं । बिहार के अंदर बिहार सरकार ने आज यह कर दिया कि परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर नियुक्ति होगी तो आज इम्तहानों में गोली बन्दूक और पिस्तौल रख कर वह परीक्षाएं पास कर रहे हैं । मैं कहता हूं यह गलत है । उस एग्जामिनेशन पर अब भरोसा नहीं रह गया है । वह चोरी का है । इसलिए सर्विसेज में नियुक्ति के लिए अलग से परीक्षा लीजिए और नियुक्ति समिति में हरिजन आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी रखिए । अगर नहीं रखेंगे तो वे लोग जिन का प्रशासन पर अधिकार है वे बराबर अधिकृत रहेंगे और इन लोगों को बराबर इस से बाहर रखेंगे । इसलिए एप्वाइंटिंग एथारिटी चाहे वह पब्लिक सर्विस कमीशन हो या कर्मचारियों के लिए हो, अधिकारियों के लिए हो, उन सब में इन वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो इन को न्याय नहीं मिल सकता है । आप के इरादे साफ रहने के बाद भी, आप की नीयत साफ रहने के बाद भी आप की नौकरशाही इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी । आप सचमुच में जिस दृढ़ता, सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार आगे बढ़ाना चाहते हैं उस के लिए जो कार्यक्रम ला रहे हैं केवल उन कार्यक्रमों को बनाने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उन का कार्यान्वयन करने से और कार्यान्वयन करने के लिए मैंने बताया कि यह तरीका आपको अपनाना पड़ेगा ।

आज आप आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, सामाजिक विषमता को दूर करने की बात कर रहे हैं । होना चाहिए, जरूरी है । लेकिन मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि 30 साल तक तो उन लोगों ने समय बर्बाद किया । आज कम से कम हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अभी प

[श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा]

शुद्ध जल की व्यवस्था कर दें। आप करना भी चाहते हैं लेकिन मैं देहात से आता हूं, मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं कि हैंडपाइप कारगर नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि तमाम जगहों पर आपने स्टेट ट्यूबवेल्स बनाए हैं जिसके कारण पानी का लेविल बहुत नीचे चला गया है। ऐसी हालत में आपकी हैंड-पाइप की योजना सफल नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि आप पाइपों के द्वारा जल की आपूर्ति करें तभी मैं समझता हूं इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है। आप जानते हैं पानी की ज्यादा जरूरत उस वक्त होती है जबकि गर्मी आती है। पहाड़ी इलाकों में बीस फिट डायमीटर के जो कुयें बनाए जाते हैं उसमें पानी नहीं रह सकता है। ऐसे स्थानों पर पत्थर काटने वाली बोरिंग का सामान ला करके आप पानी की व्यवस्था करेंगे तथा पाइप के जरिए से जल की आपूर्ति करेंगे तभी आप शुद्ध जल दे पायेंगे। भोजन देने की योजनायें आपकी बन रही हैं, ठीक है लेकिन पहले कम से कम पानी की व्यवस्था जरूर हो जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले लोकसभा के चुनाव में ऐसा लगा कि जनतंत्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत सभी मतदान करेंगे और ऐसा हुआ भी लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह मतदान शुरू का भी था और अंतिम भी था। आज कोई गरीब आदमी अपने घर से निकल कर अपना मत नहीं दे सकता है। गोली बन्दूक के जरिए से उनको वोट देने से रोक दिया जाता है। इसके लिए आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपने लोकतन्त्र को पुनर्जीवित किया है तो इसको कायम रखने का एक ही तरीका है कि सभी के लिए अपना मत डालने देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार की स्थिति के बारे में हमारे मण्डल जी परिचित हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 मार्च, 1977 को हमारे क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हुआ था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चतरा के अंदरगंज थाने के ओरमाई बीहू मतदान केन्द्र में जोकि हजारीबाग जिले में आता है, मेरे दो पोलिंग एजेन्ट्स माधी सिंह और जवाहर सिंह, जोकि कहार जाति के थे, उनकी कांग्रेस के गुंडों ने बूथ में ही छुरा मार कर हत्या कर दी। वे लोग एकमात्र घर के कमाने वाले थे। लोग एकमात्र घर के कमाने वाले थे। उनके सम्बन्ध में मैं उस उस समय से लेकर अब तक गृह मंत्री भारत सरकार तथा मुख्य मंत्री, बिहार सरकार को लिखता रहा हूं, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग एजेन्ट नियुक्त करने का अधिकार है, माधोसिंह और जवाहर सिंह ड्यूटी पर मारे गए हैं इसलिए कम से कम कुछ सांत्वना उनके परिवारों को दी जानी चाहिए। उस समय उनके बच्चे छोटे थे, अब काम करने लायक हो गए हैं। मैंने लिखा कि उनके लिए नौकरी की कोई व्यवस्था कर दी जाए लेकिन मुझे दुःख है कि मेरे बार बार लिखने के बाद भी उनके परिवारों की रक्षा करने में तथा अपने कर्तव्य पालन में सरकार असमर्थ रही है। उनके बच्चे दाने दाने के लिए घूम रहे हैं लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है। मैं चाहूंगा गृह मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देकर समुचित व्यवस्था करने का प्रबंध करें।

SHRI NIHAR LASKAR (Karimganj): Sir, my name is on our list...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You say 'your list and my list'. I know what lists are here. I am calling Mrs. Mohsina Kidwai. (*Interruptions*). I say the lists are not to be discussed on the floor of this House. It is a very bad practice. And everybody is being called according to the turn and for your information your Party has already exhausted its time. You may be alled, that is different.

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मैं आप की बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे थोड़ा वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के बजट पर बोलने के लिए दिया है।

दो, तीन बातें मैं आप के माध्यम से सदन को कहना चाहती हूं। पुलिस विभाग वह विभाग है जो अवाम की जान व माल का मुहाफिज समझा जाता है और अवाम की जान व माल के मुहाफिज ही खुद राहजन और डाकू बन जाएं, तो अवाम किस के सामने अपनी फरियाद ले कर जाए। मैं आप को बताना चाहती हूं कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट को जो बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती थी, सब से पहले जो उन की ट्रेनिंग होती थी, वह यह होती थी कि पुलिस के लोगों को अवाम से कितनी दूर रहना है, अवाम और पुलिस के बीच में कितनी बड़ी एक खाई होनी है और उसी खाई के बढ़ते बढ़ते जब लाल पगड़ी वाले सिपाही गांव में आते थे, तो गांवों के लोग उन्हें देख कर अपने घरों में छिप जाते थे। आज भी वही हालत है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि गलती किस की कहां है लेकिन मैं सरकार से यह दरख्वास्त जरूर करना चाहती हूं कि वह गंभीरता के साथ इन तमाम प्रश्नों पर विचार करे कि आखिर पुलिस के लोग इतने बदनाम क्यों हो रहे हैं और इतना डर और इतना भय अवाम को उन से क्यों होता है ? जो हालत पुलिस की ब्रिटिश पीरियड में थी, वही अब भी है। हम तो यह चाहते हैं कि जब पुलिस के लोग जाएं, तो अवाम यह समझे कि उन के मुहाफिज आए हैं, उन की मदद करने के लिए ये आए हैं। उन के सिर पर डंडे बरसाने के लिये नहीं आये हैं। इसलिये पुलिस की ट्रेनिंग में जरूर कुछ परिवर्तन आना चाहिये। उस की ट्रेनिंग के लिये समय-समय पर जो कमेटीज बनी हैं और उन्होंने जो रिकमेंडेशन्स की हैं, उन के ऊपर हमें जोर देना चाहिए और हमें पुलिस के उन कांस्टेबिल्स के हालात की तरफ भी देखना चाहिए जिन हालात के तहत वे काम करते हैं।

अब मैं अपने प्रदेश के मुताल्लिक कुछ कहना चाहती हूं। टूटे हुए थाने हैं जहां पर पानी टपकता है। दिन भर मेहनत करने के बाद एक शख्स आता है और वह रात में सो भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता और लेट भी नहीं सकता और न वह अपनी फैमिली को रख ही सकता है। न जाने इस किस्म की कितनी और चीजें हैं, जिन की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में जो छोटे कर्मचारी हैं, उन की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही हालत सी०आई०डी० के लोगों की है। उन के लिए घर नहीं हैं, क्वार्टर नहीं हैं और इस का नतीजा यह है कि वे प्राइवेट बिल्डिंग ले कर रहते हैं और जब प्राइवेट बिल्डिंग में कोई सी०आई०डी० का इंस्पेक्टर रहे या बड़ा अफसर रहे, तो वहां के वातावरण से जरूर कुछ न कुछ प्रभावित होगा।

मैं दो तीन बातें अपने प्रदेश के मुताल्लिक कहना चाहती हूं क्योंकि समय कम है। मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं उस बदकिस्मत प्रदेश से आती हूं जहां पर अब तक 50 मर्तबा फायरिंग हो चुकी हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उस को मैं ने पढ़ा है। मुझे खुशी है कि इस में यह व्यवस्था की गई है कि एमर्जेन्सी के जमाने में जो लोग पुलिस की गोली से हलाक हुए, उन के परिवारों को सरकार पेंशन देगी। बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं सरकार से यह सवाल करना चाहती हूं कि इमर्जेन्सी के वक्त जो लोग पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए, पुलिस की गोली से हलाक हुए क्या उन का खून खून था और आज जो लोग पुलिस की फायरिंग से हलाक हो रहे हैं, उन का खून पानी है, उन के जिस्म में खून की जगह पानी है। क्या उन की फैमीलीज नहीं हैं, उन के बीवी बच्चे नहीं हैं या लड़के नहीं हैं। यह डिस्क्रीमिनेशन आप क्यों करते हैं। सरकार क्यों नहीं यह एलान करती है कि जो पुलिस की फायरिंग में मरेगा, उस के परिवार को हम सहायता देंगे और वही फैसिलिटीज देंगे जो एमर्जेन्सी के वक्त में फायरिंग से मरे लोगों को दी हैं। मैं आप से कहना चाहती हूं कि इस सदन में इमर्जेन्सी के जमाने की बहुत चर्चा की गई। मैं दो, तीन वाकयात आप के सामने रखना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि इस में जर्रा बराबर भी एग्जाजेशन नहीं कर रही हूं। आपके पड़ोस में हरिद्वार है जो जिला सहारनपुर में है। वहां ज्वालापुर में 26 जनवरी को एक झंडे का कांड हुआ है। हमारे मिनिस्टर साहब ने या इस सदन में जो दूसरे सदस्य बैठने वाले हैं, उन्होंने कहीं किसी अखबार में उस की चर्चा सुनी ? मैं खुद वहां गई थी। आप एमर्जेन्सी का रोना रोते हैं। अभी भी एक थाने में हमारी कांग्रेस के एक वर्कर की दोनों हड्डियां तोड़ दी गईं। यह सब आप की नाक के नीचे जनता पार्टी के शासन में हो रहा है। किस तरह से बर्बरियत का ... का हमारे वर्कर्स को निशाना बनाया गया। हमारे साठ वर्कर्स को पकड़ कर के बंद किया गया। झंडे का मसला था। इस के पीछे कौन लोग थे। वही आर० एस०एस० के लोग थे। जब कि यह तय किया गया था कि कोई झंडा फहराये, नेशनल फ्लैग फहराये फिर यह सब हादसा हुआ। अगर इसको कोई दूसरी पार्टी करती है तो आप उसके ऊपर तवज्जह नहीं देते क्योंकि वहां लोग चाहते थे कि वहां कांग्रेस वर्कर्स को मारा जाए, पीटा जाए। उनको डरा कर, धमका कर बंद किया गया। न सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स को बंद किया गया बल्कि एक अखबार वाले को भी उनके साथ बंद किया गया। जब डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को यह मालूम हुआ कि एक अखबार वाला भी बंद है तो डी०एम० ने अखबार वालों को बुला कर छोड़ा। उसका सबूत यह है कि किसी अखबार वाले ने उस मसले पर नहीं लिखा। आप एमर्जेन्सी का रोना रोते हैं कि अखबारों पर जेन्सरशिप था। आप के टाइम पर भी यही हालत है।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

एक महीने तक हमारे वर्कर्स सहारनपुर जेल में बन्द रहे उनकी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं करा सके, हाई कोर्ट से जमानत करायी गयी। इस वक्त हमारे वर्कर्स, हमारी शक्सियत पर जो हमले किये जा रहे हैं, उनको जिस तरह से झूठे मुकद्दमों में, झूठे इल्जामात में फंसाया जा रहा है, वह सारी चीज आजकल हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है।

आज बड़े जोरों से यह कहा जाता है कि इस सरकार ने जम्हूरियत को बहाल किया। इस सरकार ने लोगों को आजादी दी। आज लोगों को सिर्फ इस बात की आजादी है कि जिस को चाहो मार दो। अगर आज कोई चीज सस्ती है तो वह जान सस्ती है। मैं आपको कितने वाकयात गिनवाऊं ? सुरेन्द्र बिक्रम जी यहां बैठे हुए हैं (व्यवधान), मैं समझती थी कि वे खुद शाहजहांपुर स्टेशन के वाकयात को बतायेंगे कि किस तरह से मिलिट्री के एक स्वीपर की बीवी को रेलवे की पुलिस फोर्स के आदमियों ने रेप किया और उसको मार कर डाल दिया। अभी आपने बस्ती में किस तरह से नर्सिज के साथ जुल्म हुआ, उसको जाना होगा। मुझे श्री गौरी शंकर राय से यह तवोक्को थी कि वे इस मामले में कुछ कहेंगे। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में सोशल वेल्फेयर डिपार्टमेंट की मिनिस्टर थी तो एक झूठे केस के बारे में सी० आई०डी० की इंक्वायरी हुई थी तो उन्होंने पूरा सदन सिर पर उठा लिया था। आज उनके पड़ोस में इस तरह के हादसे हो रहे हैं और वे खामोश हैं। आज कितनी ही पुलिस की बर्बरता और जुल्मों की कहानियां गूंज रही हैं। पुलिस ने अलीगढ़ में क्या किया ? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि वहां के हादसे में पुलिस शामिल थी। मुझे वहां के लोगों ने आ कर बताया है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ ? मैं पटेल साहब से पूछना चाहती थी, लेकिन वे शायद बताना न चाहें क्योंकि उनके मिनिस्टर साहब जो आगे बैठे हुए हैं, वे बहुत कुछ कह चुके हैं। क्या वे पूरी ईमानदारी से कह सकते हैं माइनोरिटी के लोग जुल्मोसितम का निशाना नहीं बनाये जाते हैं ? ज्वालापुर में झंडे के किस्से को ले कर माइनोरिटीज और हरिजनों के घरों में पुलिस ने घुस कर जुल्म और बर्बरता का सबूत दिया। आपकी पुलिस जो कुछ वहां कर रही है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है।

आप कहते हैं कि आप कम्युनल दंगों को रोकना चाहते हैं। आपकी नीयत पर हम शक नहीं करते, शुबहा नहीं करते। आप कम्युनल दंगे रोकना चाहते हैं, आप हरिजनों पर अत्याचार रोकना चाहते हैं आप पिछड़े वर्गों को उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप गंभीरता से सोचेंगे कि आपके वे लोग भी शामिल हैं की आपकी सरकार में की है जो दो-कौमी नजरिये में एतकाद रखते हैं। वे लोग आपके साथ हैं जो हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो हिन्दु सोसायटी को ऊपर उठाना चाहते हैं। मुझे आप से पूछना है कि इसका रिएक्शन दूसरी कौमों पर क्या होता है दूसरे लोगों पर क्या होता है ? मुल्क में जो शिशु मंदिर चल रहे हैं उनमें किस तरह की तालीम दी जाती है क्या आपने कभी उनके सिलेबस को मंगा कर देखा ह ? क्या आपने सोचा है कि वहां क्या चीज पढ़ाई जा रही है उन नन्हें-मुन्नों के दिमाग में किस तरह के बीज बोये जा रहे हैं ? उन्हें किस तरह के आदमी बनाया जा रहा है ?

आज हमारे देश में हमारे प्रदेशों में गुण्डा-गर्दी है। ये गुण्डागर्दी करने वाले कौन लोग हैं ? ये वे लोग हैं जिनको इनकी शाखाओं में चाकू और लाठी चलाना सिखाया जाता है। जिनको चाकू और लाठी चलाना सिखाया जाएगा तो चाकू और लाठी से तो सीमाओं की रक्षा नहीं होती उनका तो इस्तेमाल मोहल्लों "और कूचों में ही सकता है। जब तक आप उन पर रोक नहीं लगाते तब तक यह सारी की सारी परेशानियां कम्युनल परेशानियां दंगे फसाद आप नहीं रोक सकते हैं। आज आप कहते कि जिस वक्त हमारी जनता पार्टी की सरकार आयी है उससे वक्त से हमने अपने घोषणापत्र के मुताबिक माइनोरिटी कमीशन बनाया।

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का
जो चीरा तो एक कतराए खूं ही निकला।

माइनोरिटीज कमीशन आपने किस लिए बनाया है उसकी हैसियत क्या है उसकी पावर्ज और अख्त्यारात क्या हैं ? सिर्फ रिकोमेंडेशन करना ही उसका काम है। जो रिकोमेंडेशंज सरकार के माफिक बैठती है उनको तो मान लिया जाता है और बाकी जितनी होती हैं उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। उसकी जो सिफारिशें होती हैं उन पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट की रिकोमेंडेशन न आ जाए माना नहीं जाता है। अमल नहीं होता है। अलीगढ़ में हुए रायट्स की तफ्सील में मैं जाना नहीं चाहती, लखनऊ, बनारस आदि जहां जहां हुए हैं 'और उनके बारे में जो रिपोर्ट्स हुई हैं उन पर आपने कोई एक्शन लिया है क्या ? क्या माइनोरिटी कमीशन के बारे में सरकार सीरियस थी ? इस सीरियसनैस का तो इसी बात से पता चल जाता है कि साल के बाद तो इसको बनाया गया और उसके बाद भी न उसके आफिस का पता पता था और न उसके बैठने की कोई जगह थी। कुछ भी नहीं था। अब शायद उसको जगह मिली है। इसके बाद साल में उसका दूसरा चेयरमैन आ गया है। उसके अख्त्यारात क्या हैं, पावर्ज क्या हैं, वह क्या कर सकता है, इसको आप बताते ही नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है। नार्दर्न इंडिया से मैं अकेली हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ आठ मिनट आपकी पार्टी के बचे हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं अकेली नुमाइंदा हूं यहां और उस स्टेट से चुन कर आई हूं जहां रोज कुछ न कुछ होता रहता है। मैं बीस जनवरी के टाइम्ज आफ इंडिया में जो आंकड़े छपे हैं उनको आपको बताना चाहती हूं ताकि हमारे मिनिस्टर साहब को अंदाजा हो जाए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो रही है :

> "A cognizable offence every 3 minutes; a burglary every 15 minutes; a riot every 45 minutes; an armed robbery every hour; a dacoity every two hours and two murders every 3 hours. This is the day's average crime tally in U.P."

इससे साफ आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां की हालत कितनी खराब है। आपका विभाग तो पता नहीं कहां है। स्पेशल कोर्ट बिल पर लगा हुआ है। अपने पड़ोस में आप देखें सबकांटिनेंट में देखें कि क्या हुआ है। खबर है कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई है। आप भी अपने आपको इस तरह की फोर्सिस से आगाह कीजिये उन ताकतों को आप अपने अन्दर झांक कर देखिये जो आपके ही अन्दर छिपी हुई है, उनको देखिये जो जातपात के झगड़ों में इस मुल्क को अकेलना चाहती हैं, उनकी तरफ देखिये जो कम्युनलिज्म इस देश में लाना चाहती है, उनकी तरफ देखिये जो महात्मा गांधी की कब्र पर जा कर कस्में खाने के तो सारे काम करती हैं लेकिन वे सब काम करती हैं जो महात्मा गांधी को सख्त नापसन्द थे। महात्मा गांधी के नाम को आप न बचें। सच्चे मायनों में उनके सपनों को आप साकार करें। जो हमारे प्रदेश में आप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वे आपको मुबारिक। हमारे प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट हो इसको भी आप देखें। आज किसी को किसी की परवाह नहीं है। आखिर यह मुल्क किस तरफ जा रहा है, प्रदेश किस तरफ जा रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है। हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्पलैस है, बामोल तमाशाई की तरह बैठी देख रही है। वह कुछ करने की हिम्मत नहीं रखती है। यूनिवर्सिटीज और कालेज बन्द हैं, लड़कों की छुट्टी है। टीचर्स का जो हाल है उसको आप जानते ही हैं आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है यह आप देख ही रहे हैं। रोज यहां डैमोंस्ट्रेशन होते हैं। एक टीचर की हालत खराब है जो अस्पताल में पड़ा है और जिस को हार्ट अटैक हुआ है। रोज कितने ही मैं कालिंग एटेंशन शार्ट नोटिस देती हूं लेकिन वे मंजूर नहीं होते हैं। क्योंकि मैं तादाद में अकेली हूं इसलिए शायद इधर ध्यान नहीं दिया जाता है।

मैं आपकी मशकूर हूं कि मुझे आपने मौका दिया।

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, consequent upon the happy return of Shri Charan Singh to the Cabinet family-fold and his simultaneous elevation to the twin Deputy Prime Ministership, may be as a side affect thereof, there has been a swapping of portfolios, and the former Finance Minister now finds himself in the position of the Home Minister.

The former Minister of money power has become, in a sense, in short, the Minister of man-power. I wonder if he has got into his stride as yet. However, I am sure that, with his background, his experience of 30 to 35 years, very varied experience as a distinguished member of the ICS—what was called in the olden days a 'Heaven-born service', the steel frame, while some cynics described it as neither Indian nor civil nor service—he will get into his stride, if he has not got into it already. The foremost task he will have to address himself to is how to bring about a clean, honest and efficient Administration. That is the biggest task that faces him. During the 30 years of Congress rule, corruption had become a hydra-headed monster, became endemic in the system of the country and more or less a way of life. The Janata Government has taken some steps, but not adequate steps so far, to eradicate this evil which cankers into our society and our body politic.

What has happened to the Lokpal Bill? It has had a chequered history. The former Government of Smt. Indira Gandhi, the ex-Prime Minis-

[Shri Hari Vishnu Kamath]

ter, had treated it with disdain. almost with contempt. Twice the Lokpal Bill was allowed to lapse. Not once, but twice—in 1970 and again in 1976—it was allowed to lapse. The present Prime Minister was the distinguished Chairman of the Administrative Reforms Commission and I happened to be a Member—from the Opposition—on that Commission. We gave high priority to that subject, to that matter, to that them. The present Prime Minister himself—the then Chairman of the Administrative Reforms Commission—gave the highest priority, top priority, red-hot priority to that subject, and the Commission produced the first of its 20 Reports; that first Report was submitted to Government in October 1966. I don't blame this Government but, partly, they are also blameworthy because last year, in August, the Joint Committee of both the Houses of Parliament presented its Report to this House, and yet there is no sign of its coming up in this Session. I do hope it will be taken up in this Session and passed in this Session by both the Houses. If there is any difficulty we can have a joint session to pass that Bill, a very important Bill. Every body is talking about the Bill outside, saying that the Janata Government is going the same way as the Congress Government in regard to corruption. So it is imperative that it should be passed in this very Session, and the first Lokpal should be appointed before the commencement of the next Session of Parliament. It is only then that there will be credibility of the Government and the people will have confidence that the Government means business when it talks of corruption.

Now, I referred to the Administrative Reforms Commission. It submitted twenty Reports in all. I would like to have a detailed statement from the Government as to how many recommendations in the 20 Reports have been accepted and how many have been rejected. I want it not today, but in course of time—not very late but as soon as possible—how many recommendations have been accepted, how many have been rejected, the reasons for rejection and how many of those accepted have been implemented or are being implemented. That should come before the House very soon.

We have to improve the Administration, particularly Police Administration. We have had the National Police Commission. It is still working, I believe, presided over by a former member of the ICS, Shri Dharam Vira—who became a Governor also, after he retired from the ICS. That Commission, I believe, has submitted an interim Report—not its final Report but an interim Report—and the papers covered many of the recommendations made by the Police Commission. The House would like to know what particular recommendations have been accepted by the Government and are being implemented.

Along with that, we should have a Prison Reforms Commission also. They are dirty, stinking prisons. During the Emergency, particularly, I had a taste of the prisons— stinking, absolutely insanitary without even the minimum standards of sanitation and hygiene. The treatment of prisoners now, at least in some of the jails, is worse than what it was during the British regime. I have been in jails, both during the British regime and now, and I can say without hesitation that the prisons of free India are being worse administered or worse run—some of the prisons in any case—than the prisons during the British regime.

I have already spokan about the necessity for eradication of corrupand the necessity of passing the Lokpal Bill. This canker of corruption has a distinguished, very old, ancestry or pedigree. In the early

forties, two big issues, two big problems, two big questions, came before Parliament, one was the pre-fabricated Housing Factory and the other was the notorious jeep scandal. If they had been handled properly by the then Prime Minister—Pandit Jawaharlal Nehru had many shining qualities but, unfortunately, he was a bad judge of men and events; that was his defect; otherwise, he had many shining qualities—then at least it would not have grown to these proportions of today. The Minister himself would know more about the jeep scandal than I do. He was then the Defence Secretary, I believe, at that time when Shri Krishna Menon was the High Commissioner in London and much was said and written about that matter. The Comptroller and Auditor General at that time, Shri Narahari Rao, recommended twice that there should be a high level inquiry into the matter. But that was not done. That is why the canker has grown.

The Shah Commission has also made a very trenchant observation. I have no time to read other matters but I would quote what the Shah Commission has said about the necessity of Government implementing the recommendations of Commissions of Inquiry. It is a rather pathetic, but trenchant observation:

> "The Commission owes it to the citizen of India to emphasise that appointments of Commissions by themselves are not enough if the Governments concerned do not follow up and implement at least such of the recommendations as are avowedly accepted by the Government."

I would like to know how many persons have been indicted by the Shah Commission and the other Commissions of Inquiry appointed last year and how many are being actually prosecuted. There have been press reports that many of those indicted are still ruling the roost in various Ministries and Departments. If that is so, it is a very unfortunate development. Therefore, I would like to know how many have been indicted and how many are being prosecuted—against whom there are F.I.Rs. and such other things going on.

Then I would like to refer, in connection with administration, to the issue of the backward sections of our society, the weaker sections, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe. I am glad, and the House also would be glad, that Government has taken a very forward stand, a forward decision, to appoint Commissions, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission instead of a Special Officer, and also the Backward Classes Commission. But that is not enough to bring these backward sections, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the Harijans and the Adivasis, into the national mainstream. Dr. Ambedkar, in the Constituent Assembly, did envisage, visualise, do dream that the reservations would not be for ever, and that these sections would join the national mainstream very soon, sooner than later. Therefore, merely appointing Commissions is not enough. There should be educational and social measures and administrative measures taken to uplift and bring these classes, backward sections, backward classes the Harijans and the adivasis, into the national mainstream. That brings me to the constitutional provisions. The constitutional provisions, Articles 330 to 334, five Articles refer to these special provisions for certain classes, Harijans, Adivasis and the Anglo-Indians and the present provision is Art. 334 which says:

> "The provisions of the Constitution relating to reservation of seats in the Lok Sabha and in the Vidhan Sabhas shall cease to have effect on the expiry of a period of 30 years from the commencement of the Constitution."

It was originally 10 years, then it was raised to 20 years and then to 30 years and now this reservation will

[Shri Hari Vishnu Kamath]

expire in 1980, just about 8 or 9 months to go. The House must take serious note of the provision and decide again whether it should extend it for another 10 years or not, because it is easy to go on extending for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years or upto the end of the century and beyond, but, in their own interest, lest it become a vested interest in backwardness, a vested interest in being a Harijan, a vested interest in being an Arivasi, they should not be a class apart, and I would appeal that they should come forward and say 'We don't want any reservation'. Here I would like to recall a scene in the Constituent Assembly when the Muslims came forward and said, 'We do not want reservation'. And there was a big ovation in the Constituent Assembly when they said, 'it should be buried with the exit of the British. Don't bother. We shall join the national mainstream' and all the safeguards and reservations for Muslims were abolished by the Constituent Assembly. Of course, it was very right and very necessary, it was just proper and appropriate to have reservations for the Harijans, Adivasis and the Backward Classes as also for Anglo-Indians for 10 years. Then it was raised to 20 years and then for 30 years. Now the House must consider seriously, an all-Parties Parliamentary Committee may be constituted for the purpose, you may have some legal luminaries and constitutional experts too, but we must decide once and for all, because I remember Dr. Ambedkar saying, 'I am servation for ever. I want my people to join the national mainstream as soon as possible, sooner rather than later.' I read it sometime ago in this very House. I have not got that now with me. Therefore, this is an important matter which should be considered by the House at the earliest opportunity.

Then, there is the question of Union Territories. I am sorry to say that sometimes stray thoughts, personal thoughts and personal views are given out or given expression to and a lot of mischief and a lot of damage results, as happened in Pondicherry....

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Especially by whom?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: By the Prime Minister. I know, I think it was not proper, and it was *unfortunate on his part to have made* that observation regarding Pondicherry when our treaty with the Government of France at that time stipulates that any change should be by public opinion. Same was the case with regard to Goa. I was in the Third Lok Sabha where we passed a Bill to have an opinion poll about Goa. If there was a provision in the treaty with the French Government, it may be negotiated with the French Government again and if that is not possible, we should stick to that provision. I know and I can foresee the day when these small units will perhaps merge with the bigger adjacent States, but we should not do it in a hurry. We should not hustle it, we should not bulldoze it and we should not steamroller it according to private whims and fancies or thoughts.

I would also like to refer to the very vital issue of decentralisation of administration. In our election manifesto we have made a clear commitment. I will read only one sentence of that:

> "Panchayat institutions and municipalities will be revitalised and vested with larger powers and responsibility so that they can play their true role as basic organs of *popular government, initiative and* planning."

Article 40 of our Constitution provides for the development and establishment of Panchayats as organs, as

units of self-Government. Also item No. 3 of the Economic Charter of the Janata Party, the Manifesto, speaks about Gandhian values of austerity, Antyodaya and a decentralised economy. Therefore, the Government should take early steps for decentralisation of the administration. (*Interruptions*).

The Government had appointed a Committee headed by Shri Asoka Mehta, one of our former colleagues in Parliament and a wellknown politician and economist. They have produced a report. I am sorry to say that it does not look upon the village Panchayat as a basic unit of self-government as envisaged in the Constitution, I personally wish that the village panchayats should be given its due place in the Constitution and we should have a five tier and not four tier pattern Centre, State, District, Block and Panchayat. We should even amend the Constitution—the lists in the Constitution—to provide for these tiers, the various entities, from Centre to State, district, block and village. I am glad that you are also nodding your head, Mr. Deputy-Speaker—and you are in agreement with me.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am nodding because your time is over.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: One or two minutes more, Mr. Deputy-Speaker. I know you also subscribe to this thesis. One last word I would say about the boundary disputes—boundary dispute, particularly, of Maharashtra and Karnataka—these boundary disputes have been there for the last twenty two years, and not much has been done. Mahajan Commission was the last to tackle this problem. Its report is gathering dust in the shelfs of the Home Ministry.

Now, Sir, there is a provision in the Constitution. Government has completely ignored the provision all these twentynine years of our Republic—28 or 29 years of our Republic. There is a provision in our Constitution. Article 263 provides for an Inter-State Council. The A.R.C.—the Administrative Reforms Commission, made a strong recommendation that this Inter-State Council should be constituted to decide on various disputes between States and States and the Centre and the States. I do not know whether that recommendations has been accepted by Government or not. I do not know as to why they could not appoint ... the Inter-State Council to study this problem and resolve it once for all. There is a lot of talk. (*Interruptions*)

Then, Sir, unfortunately, I am sorry to note that, in many of the States, though Parliament, the Lok Sabha has abolished the MISA—repealed the MISA—some time in August last year, the Maintenance of Indira-Sanjay Act—I am really sorry to state that some States have lately given birth to that kind of legislation in some feebler or milder form. (*Interruptions*)—I do not know which States. The Minister should tell us which of the States have given re-birth to the MISA in a milder form. They should tell the House as to whether all those Acts which have been passed in some States have been carefully scrutinised and examined by the Central Government and whether at least all those safeguards are there which have been provided in the Constitution in the Forty-fifth Amendment Bill. (*Interruptions*) They could be examined by a Parliamentary Committee.

One word more and I have done. The other day the Finance Minister made first a statement and two days later, the Defence Minister made a statement with regard to the increase in pensions for certain categories of personnel. There is a category also, a class of people, who fought for freedom—freedom fighters who have been given pension. Some may not have accepted. But many have, as they have no other means of livelihhod. Some of them have cheated the

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Government by giving bogus certificates. I am glad that you are looking into the matter. I hope that action will be taken against those who got it through wrongful means.

I would only request the Government that if they could increase the pensions of some categories, they should give a slight increase in the pensions of this category of people also.

One last word about the International Year of the Child. There has been so much talk about it, so far. The Home Ministry with all its ramifications, has its finger in every ministry's pie. Therefore, they can do a lot in these matters. Now, he has got the manpower to ensure the implementation. Much can be done in this regard by the Home Minister through Childrens Acts, adoption of Children Bill and a few other matters can be also taken up.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Lastly, there has been talk about reorganisation of States. It is a delicate matter but, I think, the time has come when that Leviathan State, Uttar Pradesh—some people call it not a State in India but the tenth country in the world—should be divided and re-organised on proper lines. Perhaps, it could be easily made into two States.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must conclude now.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I do hope these matters will be taken up seriously and Home Minister will function in such a manner during his tenure that every home in the country becomes a happy home, with children looking forward to a bright future, and the home being secure inside with no law and order problem outside.

*SHRI A. ASOKARAJ (Perambalur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, on behalf of All India Anna Dravida Munetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs.

At the very outset, I would refer to the deteriorating law and order situation, especially among the student community throughout the country. Sir, you will agree with me if I say that the future of the country rests upon the shoulders of the youth of the nation. If the student unrest prevalent throughout the country is not resolved forthwith, naturally the nation's future is in stake. In order to foster democracy in the country, the Government of India should remove the festering sore of student unrest in particular and the worsening law and order situation in general.

My hon. colleague Shri H. V. Kamath raised a pertinent poser—how long you are going to continue the policy of reservation for scheduled castes and scheduled tribes in representative forums like the State Assemblies and the Parliament? It is time that the Government bestows some serious thought on this question. The economic disparities and social backwardness pervading persistently among the scheduled castes and scheduled tribes even after 30 years of Independence are to be probed. We have been extending a veriety of concession for their advancement, yet they have not been able to derive the maximum benefit from them. What are the reasons for this sorry state of affairs? The Government should evaluate and exert effectively to ensure that the concessions being offered to them are availed of by them.

We have been familiar with proselitisation of people from one religion to the other. In the early days the Christian fathers used to offer many baits for those in distress and they were converted to Christianity. After their conversion, they did not overnight be-

*The original speech was delivered in Tamil.

come prosperous members of Christianity. Even after such conversion many of them used to be called by their Hindu names. Just as there are innumerable sects in Hinduism, there are so many divisions in the Christianity also. The lower caste people, who became Christians, remaine as lower caste people in the Christian community. The change of religion has not changed their economic status. The Government should look into this problem and offer economic concessions for their betterment even though they are Christians.

Similarly, the Government should inquire into the reasons for the inability of scheduled tribes to utilise the beneficial concessions being offered to them. These gullible people are being made the victims of deception being practised upon them by these greedy people around them. The Government should endeavour to clean the atmosphere of misappropriation prevailing in the areas inhabited by the scheduled tribes.

16 hrs.

We are talking about the malpractition being indulged in by the Centre. Language is the soul force of our people. The solemn assurances given day in and day out by the Centre are being flouted blatantly by the Central Government. Hindi is being sought to be imposed through hook or crook on the non-Hindi speaking people. This has created a deadly scare among the non-Hindi speaking people. The Government would be well-advised to bear in mind the serious repercussions such a thoughtless step would generate.

We are talking about the malractices and corruption that have corroded the faith of the people of the country in the administration of the country. From the lowest to the highest in the bureaucratic ladder, even for small legitimate things, the palm has to be greased. Red-tapism is the seed-bed of all the corruption in the country. Whether it is political or any other aspect of activity, the honest man always comes to grief. Inspite of tall claims of successful eradication of corruption we witness the unpleasant malpractices gaining strength from day to day. The hon. Minister should look into this and do the needful.

I would also refer to the Cauvery Water dispute here because it is an inter-State problem and it falls within the jurisdiction of the Home Ministry. If this water dispute is resolved amicably between the three States, the benefit to irrigation will be immeasurable. The agriculturists of Tamil Nadu will get water for their flds.

The Home Ministry should think of divesting itself from the unwarranted load of all powers. If such a decentralisation takes place, it will evolve a healthy federal set-up in the country. The States will be enable to solve the problems on the spots; instead of rushing all the while to Delhi seeking solutions. Some serious thought must be bestowed on this question also.

All our planned efforts have helped rich people to grow richer and the poor people to become poorer. The economic imbalance is getting widened and the gulf between the rich and the poor is getting deeper. If this is not attended to, I would like to warn of the impending revolution in the country. The misery of the people may explode into an uncontrollable revolution beyond the competence of the Home Ministry. It is not that we are the butt of ridicule of foreigners who come to India. Whether it is the railway station or the bazar, you come across the extended arms of innocent young children for alms. You feel sad to look at 3 or 4 yars old children begging with tattered clothes and dishevelled hairs. We can imagine the pangs of hunger which drive them to beg. We must do something in this International year of children. The Tamil Nadu Government is implementing successfully the Beggars Rehabilitation Scheme, which is worthy

[Shri A Asokaraj]

of emulation throughout the country. The expenditure involved in this scheme should be given as grant by the Central Government to the State Government of India. By implementing this scheme of rehabilitation of beggars throughout the country, we will not only be to earn the gratitude of these people in distress but will also earn the encomium of other nations.

With these words I conclude my speech.

SHRI ASOKA KRISHNA DUTT (Dum Dum): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wanted to say several things about the workings of the Home Ministry, but you have already warned us that we have to limit our speeches.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Actually we are exhausting the time allotted for this subject.

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT: Sir, I will try to limit my speech to only those aspects which have not already been covered by the other speakers. In fact, it is very difficult to speak after a vetaran like Mr. Kamath, because he has spoken about most of the points which I wanted to mention, but still I find there are some points which have not been covered.

There is a saying that the area below a lamp is possibly the darkest of all the places. I would like to draw the attention of the Home Ministry to the very serious condition of the law and order situation in the capital city of Delhi itself.

16.04 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

Sir, it is known to you that most of the Members of Parliament stay either in North Avenue or South Avenue. Mr. Chairman, you are one of them. I believe that in the last 4 or 5 or 6 months, the incidents of theft have become the maximum in this area occupied by the Members of Parliament. It may be even far worse in other parts of the City and other parts of India, possibly those are not taken cognisance of. I will start with my own case. There was a very serious theft in my house a little over two months ago. The police came with their usual paraphernalia, the police dog was brought and when I reached here from Calcutta the officer smartly gave me a salute, but nothing has been done beyond that. Not only that nothing has been found out, but the very manner in which the investigation is proceeding is tremendously surprising. Sir, you have had the experience in your State and I have had the experience in my State about the activities of the police. The way the police over here ignores the basic clues is simply surprising. Several clues have been given to them but they would not even follow them. The strange way of whispering that goes on between certain people of the thana and the suspected culprits is also amazing. Here is my hon. friend Shri Nathu Singh, there has been a theft in his House also. If you want, I can give you a list of at least six Members of Parliament, in whose houses the thefts have taken place during the last six months in North Avenue. Where there are criminals, there would be thefts but the Ministry must be very careful and I would urge upon the Home Minister to entrust this investigation to some very senior officer of the detective department. I will give him material, I do not want to divulge it over here and I will give it to any other hon. Member who wants it. There is a serious suspicion of colusion between a section of the authorities and those who are committing these thefts. Day-light robbery is going on. One scooter of a Member of Parliament was stolen in broad daylight from the front of his house in North Avenue. What is being done about that?

16.07 hrs.

[DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

This was about Delhi. Let us now come to other aspects which nobody else in this House has covered. The Home Minister has also come now. I believe, his junior Minister will supply him with the information that I have given about the thefts that are going on in the quarters of Members of Parliament all over Delhi.

I will now come to the Home Minister himself. While congratulating him on the assumption of his new office, I will also express my deep regret and my distress on the statement that he made immediately after the became the Home Minister. He had been to the North-Eastern part of the country. He passed through Dum Dum airport, Calcutta which is my constituency also. He had perhaps never been to West Bengal as Home Minister, he might have gone there when he was Finance Minister. While coming back or going to the North-Eastern region, he spent some time in the VIP lounge in Dum Dum airport. There I do not know on what context he gave a very big certificate that the law and order situation in West Bengal was excellent and naturally this got wide publicity in the Calcutta Press. I do not know on what basis he gave that certificate. If he had thought that the airconditioned atmosphere of the VIP lounge at Dum Dum airport had an excellent law and order situtions, I have nothing to say. It is known that he was a very renowned officer of the administrative service and if he merely relies still on whatever the administrative service tells him, I must say that we are very sorry for that. He ought to have by now realised that he is no longer the top man in administrative service; he is now a political man and is the Home Minister of India. Before making such a statement and giving such a certificate, he ought to have consulted the peoples' representatives. The manner in which he gave that statement at Dum Dum airport out of the context within weeks of his assuming office gave me an impression that he still does not have any regard for democracy or for peoples' representatives. I will just bring some specific instances before him, just to tell him the reason why I resent his statement over there. Just at the time he had been to the north-eastern India and was giving this certificate at the Dum Dum airport, a Member of the West Bengal Legislative Assembly, Mr. Kiranmoy Nanda, MLA put a pointed question to the Chief Minister of West Bengal, as to how many murders were committed, in between June, 1977 and September, 1978. The answer was that 1300 murders had been committed during that period. This is not my statement, but that of the Chief Minister of the State, to which the hon. Home Minister was giving such a blank certificate.

MR. CHAIRMAN: Please take 2 or 3 more minutes and conclude.

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT: It is a very serious aspect. I will not repeat. I will bring glaring instances from that State, each one of them of a different order—murder, arson, loot and gherao. All this information has been supplied either by MPs, our honourable colleagues or by distinguished members of the Legislative Assembly. I will not quote any other persons or from any newspaper or other sources. This information was supplied to me by this hon. Member, Mr. Kiranmoy Nanda, that out of these 1300 murders that had been admitted by the Chief Minister, the total number of arrests was only 300. Less than one arrest for every 4 murders. This is what is going on there. The majority of the murders are political murders.

Another information has been supplied by my distinguished colleague Mr. Prafulla Chandra Sen. Mr. Sen went to the district of Purulia on the border of Bihar and West Bengal to

[Shri Asoke Krishna Dutt]

hold a political meeting; and a young worker of our party, named Nemai Karmakar was distributing pamphlets, that Mr. P. C. Sen would come there and hold a meeting. That very night, he was threatened; and at the dead of the night, he was hit with a rod, and he died. No enquiry is going on about it. This has been urged in the Assembly time and again. It has been stated on behalf of the Government that the suspect could not be traced.

I will give another instance of a case from the district of 24-Parganas, which is within a few miles of the place from where the hon. Home Minister was sitting and giving the certificate. Rana Dutta Chaudhri, belonging to the *Kasbah* area of 24-Parganas, was a well-known social worker. The Chief Minister of course said that he was an anti-social person. But we consider him to be a good social worker. Some gangsters belonging to or very closely patronized by the ruling party there, murdered him. They cut his body into bits, put him in a gunny bag, came to his house, and told his two sisters—who were known to them: "We have got some very good news. First give us some money to buy sweets." The sisters thought that the local boys were joking, and they gave some money. After taking the money, they opened this bag and brought out the dead body of the brother. This case was brought over there. And this question came up in the West Bengal Legislative Assembly. And the answer given was that he was an anti-social element. I ask the Home Minister: whether he was anti-social or not—if he was an anti-social person, he should have been prosecuted, and the court would have given him a proper punishment but—who are the local gangsters to do it, because he was anti-social?

I am bringing another case from the district of Midnapore. This has been supplied to me by the hon. Member of the Legislative Assembly from that particular constituency, Mr. Janamenjay Ojha. A lot of loot and arson was going on there. The ruling party people there were indiscriminately looting the crop over there.

He went to hold a meeting over there. It was announced beforehand that he was coming to hold a meeting over there. His meeting was scheduled at 3 O'clock. He arrived there one hour before. While he was there near the place where the meeting was to be held—it was at Jeelbali, Midnapur District, Bhagwanpur Police Station—he was gheraoed over there by local ruling party people—gangsters for several hours. And only after everybody had dispersed, at night, he was released. The police was informed, but nobody came. The MLA himself was gheraoed and was not allowed to hold a meeting over there. The police did not give any help. After the MLA left, the next day, the people who had allowed the MLA to sit in their house, were mercilessly beaten. This was brought up in the West Bengal Legislative Assembly. The hon. Minister can verify it. I have given the name of the MLA in West Bengal.

I will bring another case. This has been referred to me by hon. Produlla Chander Sen, our colleague. This is in Arambagh, in Pursura Police Station, Hooghly District, in his own constituency. The present ruling party in West Bengal was miserably defeated in the panchayat elections in that area; and those who were defeated took up their vendetta against those successful candidates and against those who worked for them. On the 26th of February, 1979, after getting this certificate from the hon. Home Minister, they become more tough. After getting this certificate on the 26th February, 1979, at Pursura Police Station in Arambagh sub-division, Hooghly Distt. a medicine shopkeeper, Bishwanath Sasmal, who was suspected to have helped non-party candidates in the election, was pulled out from his shop, taken

below a bridge and was stabbed over there. The local people went there, caught some of the miscreants, kept oven there and then handed them over to the police. That case has not been proceeded with. All those miscreants who were caught red handed have been released. He was stabbed on his body and chest and is still in the hospital. Pressure is being exerted to get him released from the hospital so that the case can be completely hushed up.

Before I conclude, I will specially mention about two particular matters. These are only important things. I found that my hon. friends from the Ruling Party from West Bengal the other day, were boasting that because of their Government over there, there is no oppression on minority, there is no oppression on harijans in West Bengal. West Bengal has another tradition due to Sahajiya religion over there and the Bhakti cult and the influence of Chaitanya Mahaprabhu over there. The caste system is much less repulsive in West Bengal than may be in other parts of the country. But the way this Government is doing, I will bring one or two more instances to your notice, specially regarding oppression on minorities and Harijans. There is a place called Pansila in the Deganga Police Station. I believe the hon. Home Minister will make a note of this. It is in 24 Parganas District. There is one Anchal Pradhan belonging to the minority community. He is called 'Hakim Sardar'. He had got the guts, he had dared to disagree with the powers that be in the West Bengal Assembly. As a result of that, in a broad day light, a group of gangsters from the ruling party came and set fire on his house. Hon. S. K. Sarkar M.P. and Hon. M. A. Hannan had just now handed over to me some pages of the holy Koran Sherif that were burnt by the ruling party in West Bengal Assembly in the house of Hakim Sardar.

Lastly, I will discuss about the matter of Marichjhanpi in the southern portion of 24 Parganas. A group of MPs, among us, from both sides of this House, had appealed to the Speaker to send a parliamentary commission over there. Ultimately, no parliamentary commission was sent. The Prime Minister had sent three members of the Ruling Party to find out the facts about the atrocities committed by the State Government on the Harijan refugees. The Prime Minister in his wisdom had not sent any of us, who come from West Bengal; he had sent colleagues from other parts of India so that no question of bias may come in. What happened? A report will come from them; none of them have told me anything because they have to submit their report. I will only say what has been said by Shri Shakti Kumar Sarkar, a colleague who is present here, by the leader of the Opposition in the West Benbal assembly Mr. Kasi Kanta Moitra and the Deputy leader of the Janata party Professor Prabod Chandra Sinha in the Legislative assembly of West Bengal. They had accompanied the hon. Members of Parliament to Marichjhapi. As soon as they started police launches started following them. They thought that it might be for the purpose of their security that they were coming. But after the launch reached an area next to Marichjhapi, an area which is called Kumir Mari, just before that the police launch lassoed the launch which was carrying the Members of Parliament and arrested the launch and kept them detained for almost half an hour. Then they were released after long arguments. After a little while they were lessoed and arrested again and kept over there. After that when the Leader of the Janata Party Parliamentary delegation exerted his influence and talked very hardly and strongly about this, then only the launch was released, but it was surrounded by about 7 or 8 police launches. A full report will come from the hon. Members of Parliament themselves and we will demand a full discussion in the House and we will have a full debate over this matter.

[Shri Ashoke Krishna Dutt]

There are two very significant matters. One is that if a team of Members of Parliament sent by the ruling party, nominated by the Prime Minister can at the sweet will of the state Government be prevented from enquiring properly into those things and the police can become so arrogant over there to arrest the Members of Parliament at their sweet will off and on, it must be stopped. I should like the Home Minister to take keen note of another aspect of this matter, the morale and the esprit de corps of the Indian Administrative Service.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI ASOKE KRISHNA DUTT: It will have reflection all over the country. I will conclude in just two minutes. The Home Minister and the Government ought to take serious note of the fact that the esprit de corps of the Indian Administrative service officers and of the Indian police service officers is being completely denigrated; they are being reduced to something worse than vassals. I must say that this is a tradition that was being carried on from the last administration; the great dictator had reduced them to a very low morale. But now all over the country the morale has improved and the situation is better. But we are finding the same kind of tyranny in one part of the country, in the State of West Bengal from where we have been elected. We feel that this has to be curbed immediately. The Home Minister has the authority; the administrative services and the police service are of All India character. What do they care about the illegal orders given to them by the local government? The local government must give legal orders. The Government of India must take notice of this aspect of the Members of the administrative service and the police service and give them the courage so that they can refuse to carry out illegal orders given by any state government which may be over there.

I am impressing this point upon the Home Minister and urging upon him to do something to rectify the certificate that he had inadvertently given them; he should go to the state himself and make a thorough enquiry and be himself satisfied before he gives certificates after hearing somebody else or appreciating the air conditioned atmosphere of the VIP lounge of the Dum Dum airport.

SHRIMATI AKBAR JAHAN BEGUM (Srinagar): I come from very small State of the country—Jammu and Kashmir State. In terms of population and material resources, etc., it is small yet it is not small in terms of ideals and values its people have upheld and sacrificed for. What are those ideals? They are to erect and sustain the edifice of human brotherhood, of secularism—of social and economic justice. May I remind the Hon'ble Members that this State was the first to implement land reforms and to end various forms of exploitation, feudalism and all that goes with it. It was the first to demand the abolition of personal rule of Maharajas and Nawabs who do not seem to forgive them for this. Hon'ble Members know that the people of the State have faced and are still facing a challenge to these ideals—a challenge to the essential unity underlying the ideal of human brotherhood. We hold that the pursuit of ideals of secularism, socialism and democracy are not only basic and fundamental for the life of the people of Jammu and Kashmir but are the bed-rock for the whole of the country. The State is so important an integral part of the Nation not only because it is strategically situated but more so because it has to be a model for secularism, for socialism and economic justice and for democracy. What is that which draws the people of the State nearer and nearer to the rest of the people of our Nation! It is the democratic way of

life—it is secularism—it is human brotherhood.

My colleague, Dr. Karan Singh, has a few days back, made some complaints in this House. He has tried to create misunderstandings and prejudices. Before doing so, he professed that National interest was uppermost in his mind. Yet what he has been doing and saying—what he has been encouraging by his financial resources is gravely endangering these very interests.

It is now common knowledge that he is creating law and order problem in Jammu in the name of removing imbalances, which he alleges are present. He knows fully well that what Jammu got and has achieved in economic development far exceeds that of Kashmir Valley. He knows also that out of about 7,400 persons in the gazetted services in the State, as many as 4,300 i.e. 57 per cent are manned by non-muslims. He is not satisfied to a probe into the question by Janata legislators. What is done is to whip up regional and rather communal sentiments in order to carve out a separate authority in Jammu.

Hon'ble Members know that the stir in Jammu has been confined mostly to the districts of Jammu, Kathua where campaign has been launched to create gulfs of prejudice and misunderstanding. What is the purpose! The whole purpose is to coerce the State Government and the Central Government to accept the demand or creating a separate set-up of authority in Jammu. What has been the reaction in the other three or four districts of Jammu—viz. Rajouri, Doda, Poonch and Udhampur where the population is predominantly Muslim? They are dead against being dominated by and coming under what they call hegemony of Jammu town.

Dr. Karan Singh has accused the Central Government for allowing disturbances effecting law and order. The boot is on the other leg. It is well known that through his financial resources he is recruiting teen-agers to burn property, pelt stones, stop students from going to colleges and schools. After the forced closure of schools for three months, the people of Jammu approached the State Government to prevent such hooligans from their activities and open the schools. The schools opened but an hon. Member of this House, Mr. Baldev Singh, who is sitting here today, on the advice of Dr. Karan Singh went door to door and prevented the students from going to schools... (*Interruptions*).

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): I deny it; it is false. I should be given an opportunity to rebut it.

सभापति महोदय :—आप अपनी बारी पर बोलें, अभी उनको बोलने दें ।

SHRIMATI AKBAR JAHAN BEGUM: I wish the hon. Member knew how to behave in Parliament specially when a lady is speaking.

The hon. Member has the cheek to accuse the Central Government of neglecting the law and order! Can hypocrisy pay?

What is the purpose and aim of this stir. Under the garb of removing imbalances, a campaign of coercion has been launched against the duly elected Members of Legislature to amend the State Constitution in order to set up a dual authority in Jammu, parallel to the democratic set-up over which some politicians dream to preside. The plea has been raised that the Kashmiri Muslims are dominating and others have not got their due. Though to approach the problems the communal angle would be against the very spirit of secularism yet in order to refute this allegation I would like the hon. Members to take note of the following....

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA: It it pertnissible to read a statement like this?

सभापति महोदय :—उनको अपने विचार रखने का हक है, आप कृपया शांत रहें।

SHRIMATI AKBAR JAHAN BEGUM: I am quoting figures. (a) Out of 7382 officers in the State gazetted cadre, as many as 4300 are Hindus.

(b) Our of 1896 students deputed for training in various courses 971 are Hindus mostly from Jammu.

(c) From 1975 uptodate 5321 persons were employed by various recruitment boards in non-gazetted cadre. Out of them 3070 are Hindus.

(d) For Jammu Division Rs. 44 crores were allotted for development purposes while the share of Kashmir was only Rs. 40 crores.

It is pertinent to note that those elements in Kashmir which have always thought that Kashmir and Jammu should be separated to pave the way for a very loose control in Kashmir, are happy at such developments in Jammu. I ask; are such trends consistent with our national interests and those of the security of the country?

It is very unfortunate that persons who call themselves responsible must be misrepresenting facts. It has been said in this House that the Government has seven Cabinet Ministers, out of whom only one is from Jammu. The impression is thereby created that only one Hindu is in the Cabinet. The fact is that the Cabinet has six members out of whom three are Muslims, two are Hindus and one is Buddhist from Ladakh. It has been said here that there are hardly any Hindus in Kashmir except Kashmiri Pandits. This is not a fact, we are proud of the Kashmiri Pandit community from among whom very illustrous persons have rendered yoeman service to the nation. The Hindus in Kashmir are an important segment of our population, advanced in education and other qualities. It is wrong to say that there are no Hindus in Kashmir, though Muslims are 90 per cent. In Jammu also the Muslims constitute about 33 per cent.

It is incorrect to state that the National Conference Party is confined to Kashmir only. In the last election it won seven seats in Jammu and secured 47 per cent of votes polled in the division. While I would not like to go into the details, I would appeal that nothing should be done which will come in the way of integrating various sections of the population into one whole. That is the demand of the ideal of secularism and national integration. Any demand for setting up a separate authority in Jammu would mean a chain reaction in the whole of the country. May I join with the appeal made by some national dailies, who cautioned these elements and remarked 'Don't play with fire".

I would also like the hon. Members to know that a Private Members' Bill, introduced by Shri Mangat Ram of Congress (I), is pending with the State Legislature. It seeks to do away with Dharmarth Trust being managed by one single trustee, who, it is alleged, is not using the income of the Trust for charitable purposes only. Shri Karan Singh is unhappy over it and has accused the Government on this account. If it is public property, its income has to be used for public purposes, but that is a matter for consideration by the Legislators.

It is regrettable that a responsible Member of this House should advise the Government to ignore what is happening by way of violence resorted to by teenagers, who hardly know what is the purpose of the agitation. There is irrefutable evidence of the fact that these very persons who proclaim themselves to be patriotic and to be believing in lawful means are

creating this stir in Jammu, which is confined to some teenagers.

I would like to state also that the question of jurisdiction of the minority Commission in the State is being looked into by a Committee of Legislators. On this account also it has been sought to create misunderstanding, but these are small matters. Let us all join to create more peaceful conditions in Jammu and stop the fissiparous and divisive trend which has been let loose.

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): Madam Chairman, the Home Minister is the backbone of the entire governmental structure. On its proper functioning depends not only the peace and security but also the progress and prosperity of the country. It is not only responsible for the maintenance of law and order but also for seeing that the rules of the game are being properly observed, and not violated, grievances are redressed and justice reaches the common man. In order to have a just society it is not only essential that the law must be good, but they must be impartially administered because the image of the Government depends on their proper and just implementation.

Before I come to the other aspects of the matter, I would like to say something about the police, which has been the most maligned department about which there has been a lot of criticism. I do not say that there is nothing wrong with it at all. Everybody feels that there is something seriously wrong with the system and the machinery who are entrusted with the maintenance of law and order and giving peace and tranquility to the country. Some aspects about the conditions of their work and the history of this force have been mentioned. The conditions in which they work and the past history of how the force has been created—this is all mentioned. But there are certain other aspects to which I would like to draw the attention of the House. One is that in most of the issues that come up for discussion, the role of the police is not judged fairly and impartially, but it is politicised and that is one of the greatest handicaps that prevents the right thing being done in these matters. Unbridled criticism causes demoralisation in the force. In the circumstances how is it possible for any force to work effectively? If the police acts effectively, then it is charged with excesses. If it restrains its hadn then it is chaged with inaction or softness. By and large, police is held guilty of using force when tackling criminals or bad characters but when a theft is committed in one's own house, our attitude changes and we say that the suspects are not effectively dealth with and sufficient pressure has not been applied to work out the crime and recover the property. These duel standards do not help.

I will give you an idea how the police officers feel about it so that the thing can be brought out in the proper prespective. Here is what Mr. K. F. Rustomji, a Member of the National Police Commission, says:

> "The basic defect of our entire criminal justice system is that it is all slanted against the poor. But there are other defects which make a change imperative. There are few countries in the world, where justice is so easy to evade for a man with money. There is no other country where a poor man who is caught in the coils of the law finds it so difficult to extricate himself from the simplest of crimes."

Then, Madam, he goes on to say:

> "There is no country where lawbreaking and politics are synonymous; none in which students and several other groups are above the law—they can start riots, uproot the railway line, burn buses

[Shri Shambhu Nath Chaturvedi]

and even whole streets, and then say, "Sorry", and get back to work". This is what is happening every day. "There is no country, perhaps, in which conviction in a court of law is so difficult, so best with appeals to higher courts, petitions of various types, interlocutory petitions, stay orders. writs and there is no democratic country in which Government depends for its stability, not on a well-organised criminal justice system, but on the power of the police to deal with dissent in a rough manner."

It may also be pointed out that now the sphere of activity of the police has considerably enlarged. The strength of the police has not increased commensurately. The policy has also to carry the load of the sins of most of other departments, for grievances supposed or real, and for decisions taken elsewhere, in which the police had no hand or part. It is not responsible at all for the rights and wrongs of the matter, but because it is the enforcing agency, it incurs all the odium. We must realise this before we charge the police with partiality or excesses. It is easy to sit inside a cosy drawing room and make a judgement, but actually when things happen on the streets, when property is being destroyed, when fire is being set to houses, when people are pelted with stones, to keep your composure and deal with the situation on the spot is quite a different thing. Actually, this is what is happening, and I must say that we must be very clear in our mind about this. There is a lot of hypocrisy in our public life. We know that most of these protest demonstrations that are organised are going to turn violent and yet we maintain the pose of non-violence and innolence. When violence is curbed by superior violence, you cannot curb it otherwise, there is an outcry. This is most unfortunate, and duly encourages the law breakness, but nobody appreciates it. On the other hand, all sorts of wild charges are levelled against the police, not realising the circumstances in which they have to function.

Mr. Rustomji further says:

> "What is the use of talking about justice in the land if the worst enemy of justice is the law itself?"

That is because there are so many hindrances as stated above. We have never thought of removing them, and still we think that the best results can be obtained.

Then I come to the border aspect, the administrative aspect. If we have not been able to get as much credit as we should have for all the things that this Government has done, it is because with the best intentions we have not been able to implement whatever we wanted to. The entire image of the Government depends upon the administration. The task of administration has become very complicated because of the massive size and ever-expanding sphere of activity of the Government and the greater consciousness of their rights among the people. Offences have multiplied, and more time is taken on law and order questions and less on actual investigation of crimes. Since the administration touches the life of the people at numerous points, administrative justice has acquired a new dimension, and even in the highly developed and well-administered countries, the necessity of some machinery or institution like the Ombudsman has been keenly felt. This is because the common man feels completely bewildered and helpless in the jungle of laws and before the organised might of the bureaucracy. This is much more so in the poorer and developing countries. Even in the well-developed countries they have the institution of the Ombudsman. It is much more needed in this country where, because

of the poverty and ignorance of the people, squeeze nepotism, petty and large-scale graft are taken as the norms of government operation rather than the occasional exception.

The Lok Pal Bill has yet to be passed. Mr. Kamath has given its history all through the years. The Lok Ayukta Bill is now not even thought of. The recommendations of the Santhanam Committee regarding redressal of public complaints and grievances have also been put in cold storage. But even if these things take time for implementation, there is apparently no reason for such inordinate delay. There are two or three things which could be done immediately for improving administration:

(i) Ruthless elimination of delays which provide the amplest scope for all sorts of harassment and mulcting of the people;

(ii) Streamlining of the departmental machinery which has become more and more cumbersome and complicated;

(iii) Fixing of responsibility for decision making at different levels and decentralisation of authority.

"The growth in the absolute and relative size of Government," says T.A. Barrington, "in our society poses, therefore, two or three important problems, viz., the clogging of the centres of decisions, the atrophy of the periphery and the bureaucratization of decision-making in Society. On sees no evidence that any real attempt is being made to adapt our administrative and political system to cope with these problems. The complexity baffles the citizen or the group and it makes it extremely difficult to initiate development. The remoteness of the centres of decision and the devision of responsibility between so many bodies make for irresponsive administration and for frustrated citizens."

One word about political pensions, which are now being revised after a lapse of a number of years. They are being reconsidered. The political pensioners are supposed to give fresh evidence of their political suffering. I think it is very humiliating.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : 75 परसेंट गलत है ।

SHRI SHAMBU NATH CHATURVEDI: They may be wrong. But then you should find out, but not penalise the genuine ones. If you ask them to produce fresh evidence, after thirty or forty years, of their political suffering, it is extremely humiliating, when the records too would have been weeded out.

MR. CHAIRMAN: I am calling the next speaker, Shri Asaithambi.

*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Madam Chairman, the hon. Member, Shri M. N. Govindan Nair, who preceded me, pointed out the pernicious attempts on the part of the Home Ministry to establish a Hindu Raj in India inhabited by people of different ethnic and religious groups like Sikhs, Buddhists, Christians etc. I would like to make the allegation that the Home Ministry is also conspiring to establish Hindi Raj in India. I can substantiate my contention by referring to many activities of the Home Ministry which would usher in an era of Hindi Raj in the country.

Immediately after Independence, when the people were in the exuberance of newly found freedom, Hindi was declared as the official language in the Constitution of India which the people gave unto themselves. When the process of implementation started, Tamil Nadu was the first to raise the banner of protest, as the people knew that the acceptance of Hindi would herald Hindi imperialism in the country and it would hinder the establishment of democracy in the nation.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. V. P. Asaithambi]

manian and Shri O. V. Alagesan who were the Ministers of Central Council of Ministers had to resign Then, impelled by the instinctive resentment to the imposition of Hindi by the non-Hindi speaking people, Pandit Jawaharlal Nehru gave the solemn assurance that so long as non-Hindi speaking desired, English would continue to be the official language. After Pandit Nehru let us see what steps were taken to implement his assurance to the non-Hindi speaking people of the country.

On the next day of 25th June, 75 when his daughter Mrs. Indira Gandhi proclaimed Internal Emergency, a separate Department was created under the Home Ministry with 62 senior Officers to expedite the process of imposing Hindi all over the country. The inevitable consequence of this is today's directives of the Home Ministry to the public sector undertakings and the Banks in Northern India to correspond only in Hindi with the customers. They have been asked to converse also only in Hindi, as if all the people in North India are Hindi-knowing people. Such a fanatic approach towards Hindi has strengthened the hands of Hindi protagonists even to embrass the President of India in the public functions attended by him. In his august presence, they spoke in chaste Hindi and chased away the geniality of our President. Even when the first citizen of India has been made the second-class citizen, you can very well imagine the plight of non-Hindi speaking people.

I have to warn the Home Minister that if such efforts persist, then he will be paving the way for partitioning the nation into Hindi-speaking area and non-Hindi speaking area. I am sure he will not become a party to such an unwise move.

I am demand that a parliamentary Committee comprising the non-Hindi speaking Members of Lok Sabha should be constituted to supervise the implementation of the solemn assurance of Pandit Nehru to the non-Hindi-speaking people, to safeguard the interests of non-Hindi speaking people and to strive for sustaining the integration of the nation. If this is not done the unity of the country will be disrupted beyond repair.

With these words I conclude my speech.

MR. CHAIRMAN: The hon. Home Minister.

SOME HON. MEMBERS: *rose*—

SOME HON. MEMBERS: The time may be extended.

SHRI K. GOPAL (Karur): What about our party's time? We have got still 15 minutes more. Let him reply on Friday. I take very serious objection to this.

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? When the Chair is standing, nobody else can stand.

श्री आर० एम० कुरील : (मोहन लाल गेंज) : मैं प्रस्ताव लाता हूं कि दो घंटे टाइम और बढ़ाया जाये।

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

आप लोग इस तरह से हल्ला करेंगे तो....

SHRI K. GOPAL: Don't shout like that. What is this?

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI K. GOPAL: Why are you shouting?

MR. CHAIRMAN: I wish to appeal to the House: Do you wish to respect yourselves or not?

SHRI K. GOPAL: What do you mean?

MR. CHAIRMAN: Will you please behave? This is not proper.

मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे कहना चाहती हूं कि चेयर की डिग्निटी इस हाउस की डिग्निटी है। अगर आप चेयर के साथ यह करते हैं तो मेरा अपमान नहीं करते, अपना अपमान करते हैं, यह अच्छा नहीं है। आज 2 साल हो गये है इस हाउस को अपना सम्मान, अपनी मर्यादा अपनी डिग्निटी अगर कायम रखनी है तो चेयर की मर्यादा और डिग्निटी को कायम रखना होगा। चेयर में कौन बैठा है इससे मतलब नहीं है।

मेरे पास एक लिस्ट डिप्टी स्पीकर साहब रख गये हैं। उन्होंने कहा है कि 4.50 और 5.00 बजे के बीच में मैं मिनिस्टर साहब को बुलाऊं और आवश्यक है क्योंकि मिनिस्टर को, कल तो छुट्टी है, 6 तारीख को मिनिस्टर होंगे नहीं, इसलिये आज उनका जवाब होना चाहिये। अभी और बहुत सी डिमांडज पड़ी हैं, जहां तक मुझे मालम है, डिप्टी स्पीकर साहब ने सब देखकर यह लिस्ट बनाई है

The Deputy-Speaker has made a list. He has left instructions that the Minister is to be called between 4.50 and 5.00 P.M. Further, there is a Calling Attention at 5.30 P.M. I would request the House if, the Minister takes a little more time, to please agree to take up the Calling Attention later, beyond 6 O'Clock, so that it can be completed today. I would request the cooperation and the good-will of the House. Please let the Minister now reply.

17.00 hrs.

SHRI K. GOPAL: I want to make a submission. Our party has been given some time. We have got 15 more minutes. I would like to know how you have managed the time. The time was allotted by the Business Advisory Committee and the Speaker: how are you cutting it. In that case, you should have cut the time of the ruling Party Members and not that of the Opposition. We have 15 minutes more and we must get it: that is all I say. The time was allotted by the Speaker. (*Interruptions*).

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki): In this matter, when the Home Ministry is being discussed, the Opposition has got a stake in the Demands of the Home Ministry. We had received intimation from the Speaker or the Secretariat saying that our Party has been allotted this much time. It is the vested right of the Party to have the debating time to the extent notified to us. That is the vested right of the party and if anything short of that is given, we have got a right to demand that our allotted time be given to us, and adjustments may be done otherwise. So much time is being given to Members of the ruling Party but when Members speak from here, restrictions are imposed and even the time allotted to the Party is not being allowed. This is an atrocious situation which cannot be tolerated. We function on the basis of allotment of time to different Parties and that allotted time has to be conformed to. If necessary we can sit a little more: we don't object to that. But any Party which has been given a certain time must be allowed that time and the Members must be allowed to speak for that much time. Mr. Gopal says we have been given 15 minutes less than our legitimate due. You must listen to us and Members must be allowed to take the time allotted by the Speaker. Time has been allotted by the Speaker and the Secretariat has given notice that we have so much time.

MR. CHAIRMAN: Now you are taking up so much time unnecessarily. I am only following what the Deputy-Speaker has said.

SHRI K. GOPAL: We have to follow what the Speaker has said.

MR. CHAIRMAN: Please let me finish. I am asking you to take ten more minutes and finish as quickly as possible.

SHRI K. GOPAL: We will take our due time of 15 minutes and then the Minister can reply.

MR. CHAIRMAN: I do not know that there are 15 minutes. The Deputy-Speaker has not indicated it. (*Interruptions*)

Now please start speaking instead of wasting time.

Shri T. S. Shrangare.

SHRI R. L. KUREEL: By how much time has it been extended?

MR. CHAIRMAN: One man says his time is there: therefore I am giving more time.

SHRI K. GOPAL: What do you mean by 'one man'? You are asking me to behave but you don't behave.

MR. CHAIRMAN: Please don't get so excited. Surely to be a man is greater than to be a Member of Parliament. I consider to be a man a greater compliment than just anything else and I wish we could all be real, good men and women—and that is a greater compliment than anything else.

Now please take your seats and don't waste time. Shri T. S. Shrangare. (*Interruptions*)

SHRI R. L. KUREEL: By how mush has the time been extended? We want to know first. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: It is not for me to extend. (*Interruptions*)

श्री टी०एस० श्रंगारे (उस्मानाबाद) : सभापति महोदया इस मंत्रालय की डिमांड्स पर बात करते समय बहुत से सदस्यों ने आरक्षण के बारे में चर्चा की है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं। कि 1981 में यह आरक्षण खत्म होने वाला है हम यह चाहेंगे कि जब तक इन लोगों की एकोनामिक साउंडनेस के लिए कोई सब्स्टीच्यूट व्यवस्था न बन जाये तब तक यह चलना बहुत जरूरी है। उस के पहले इसे बन्द करने से जिन के लिए यह आरक्षण मिला हुआ है उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसे खत्म करने के पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि इन की एकोनामिक पोजीशन किस हद् तक बढ़ गई है। अगर उन की एकोनामिक पोजीशन अच्छी नहीं हुई है तो उन लोगों को इस सहुलियत से वंचित कर देना उचित नहीं होगा। वैसी हालत में उन के जो बच्चे स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं उन की किसी प्रकार की प्रगति असंभव है। इसलिए उन को आर्थिक और सामाजिक तौर पर बराबर के दर्जे पर लाने के लिए जब तक कोई दूसरी व्यवस्था न हो तब तक यह चलना चाहिए।

पिछली सरकार के जमाने में सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत लाखों एकड़ जमीन सम्पादित की गई जिस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन अब पता चला है कि 50 हजार एकड़ जमीन जिस का उन को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आज उन के पास कायम नहीं है। जब तक इन सारी चीजों के लिए कोई अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं होगी तब तक उन की जो सोशल और एकोनामिक लाइफ है वह अच्छी बन नहीं सकती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उन्हें यह सहूलियत देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्शन आफ सिविल राइटस के बारे में इस सदन ने कई कानून बनाए हैं लेकिन जो नीचे वाली मशीनरी है गवर्नमेंट के नीचे जो पुलिस की मशीनरी है उस के कारण अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसलिए पुलिस के जो लोग हैं उन के ऊपर अच्छे संस्कार डालने की जरूरत है और उन के नजरिये को बदलने की जरूरत है। जब तक उन की दृष्टि उन लोगों की तरफ देखने की नहीं बनेगी तब तक इस प्रकार के एनैक्टमेंट्स का ईम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो सकता।

देहातों में आज भी पीने का पानी नहीं मिलता है। जो गरीब आदमी है वे छूआछात के कारण पीने के पानी से वंचित रहते हैं। उन के लिए कोई प्रबन्ध करना निहायत जरूरी है। तीस साल की आजादी हो गई यहां पर लोकतंत्र चल रहा है लेकिन आज भी वहां गरीब लोगों को छूआछुत के कारण मांग कर पानी पीना पड़ता है। यह बड़ी शर्मनाक बात है। इस लोकतंत्र के अन्दर हर एक नागरिक को सभी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। मगर आज भी हमारे देश में कई तरह की छूआछुत मौजूद हैं जिस के कारण इन लोगों को आज भी मांग कर पानी पीना पड़ता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर से वह कहें कि जहां पर जिन मुहल्लों या बस्तियों में पीने का पानी की सुविधा नहीं है वहां प्रायरिटी के लिहाज से पानी की सुविधा देने का प्रबन्ध करें। यह सब से अच्छा काम होगा मानवता के लिए और धर्म के लिए भी यह बहुत ही अच्छा और शुभ होगा।

कामत साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने यह कहा था कि यह आरक्षण हमेशा के लिए वह नहीं चाहते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के जिस शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम वह लेते हैं जिन के बनाए हुए संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करते हैं उन के नाम पर मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम न तब्दील करने की बात को ले कर आज फिर आन्दोलन होने की संभावना पैदा हो गई है जिस के कारण देहातों के अन्दर जो गरीब लोग हैं वे सभी भयभीत हैं। दो दिन पहले औरंगाबाद और कई दूसरे शहरों के महाविद्यालय बन्द हो गए हैं। स्थिति यह है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार ने उन के नाम से उस विद्यापीठ का नाम तब्दील करने की इजाजत नहीं दी तो फिर वहां एजीटेशन शुरू होने की संभावना है। मैं चाहूंगा कि इस एजिटेशन के गहरा बन जाने के पहले ही गृह मंत्री महोदय तथा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को इस पर खास तवज्जह देने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि आपने नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना की है। हरिजन आदिवासियों के जो पुलिस अफसर या कांसटेबिल होते हैं वे देहातों में आउट-पोस्ट या पुलिस स्टेशनों पर जाते हैं तो वहां पर उनके रहने के लिए मकानों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहां पर सरकार की तरफ से जो मकान बने रहते हैं उनमें सवर्ण पुलिस अफसर और कांसटैबिल रहते हैं और हरिजनों को कहीं बाहर जाकर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां पर जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं वह हरिजन आदिवासी पुलिस अफसर तथा कांसटेबिलों को पहले एलाट किए जाने चाहिये। अगर सवर्णों को क्वार्टर्स नहीं भी मिल पाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी क्योंकि उनको दूसरी जगह भी आसानी से रहने के लिए मकान मिल जाते हैं। इस बात पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हमारा उस्मानाबाद जिला औरंगाबाद से दो सौ किलोमीटर पर है। उस्मानाबाद में पुलिस की डाग पार्टी का होना चाहिए। अभी डाग पार्टी आने में बहुत समय लग जाता है जिसकी वजह से सर्कमस्टांशियल एविडेन्स खत्म हो जाती है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर डाग-पार्टी का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ पुलिस जो फोटो लेती है उसके लिए प्राइवेट फाटोग्राफर्स को बुलाती है। इस व्यवस्था में भी सुधार लाने की जरूरत है। एक नया सेक्शन बढ़ाकर पुलिस फोटोग्राफर की व्यवस्था होनी चाहिये क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने के लिहाज से जो फोटो लेनी होती हैं वह कोई प्राइवेट फोटोग्राफर खींच नहीं सकता है। इसलिए पुलिस में स्पेशल फोटोग्राफर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके साथ ही आज हरिजनों पर जो सोशल एट्रासिटीज होती हैं उन केसेज को ट्राई करने के लिए मोबाइल कोर्ट्स की स्थापना की जानी चाहिए। आजकल जो कोर्ट्स हैं उनमें काफी केसेज होने कारण इस तरह के केसेज को ट्राई करने का समय नहीं मिल पाता है उनको ट्राई करने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए सोशल आफेंसेज को ट्राई करने के लिए मोबाइल कोर्ट्स की बहुत जरूरत है। इस पर मंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही एक बात यह भी है कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी शिक्षा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। जो राज्य की भाषा होती है उसमें पुस्तकें होने के कारण वे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं। जब तक आप वर्नाक्यूलर और अन्य लैंग्वेजेज में किताबें वगैरह नहीं तैयार करवाते हैं तब तक पिछड़े समाज को दूसरों के बराबर लाने में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स का जो कानून इस सदन से पास हुआ है उसका प्रापर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। समाज में जब तक सोशल स्टैबिलिटी नहीं आती है तब तक पोलिटिकल और एकोनामिक स्टैबिलिटी भी नहीं होगी। एक स्थान पर भोजन करने से जातीयता नहीं मिटेगी क्योंकि यह बीमारी दिमागों में बहुत सालों से बैठी हुई है। जब तक यह बीमारी नहीं मिटेगी तब तक इस देश में एकता की भावना का निर्माण होना सम्भव नहीं है।

मैं ने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं मैं आशा करता हूं कि उन पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। आपने मुझे दो मिनट ज्यादा दिए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN: The hon. Home Minister.

SHRI H. M. PATEL: Madam, Chairman.... (*Interruptions*)

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu): Certain allegations have been made on the floor of the House. (*Interruptions*)

श्री हीराभाई (बांसवाड़ा) : मुझे भी थोड़ा समय बोलने के लिए दीजिए।..(**व्यवधान**)..

श्री आर० एल० कुरील : मैं पूछना चाहूंगा कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ...(**व्यवधान**)...

श्री राम देनी राम (पलामू) : हमें इससे विश्वास कैसे होगा। हमें बोलने का मौका नहीं मिला और जो समय दिया गया है वह पक्षपातपूर्ण है।..(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह कितनी बुरी बात है। इस के लिए इतना टाइम बढ़ा है और अभी भी लम्बी लिस्ट पड़ी है और इन सब को नहीं बुलाया जा सकता। मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं और आप सुनें। आप ऐसा क्यों करते हैं।

मिनिस्टर साहब शुरू करें।

श्री हीराभाई : राजस्थान का एक ही सदस्य बोला है। इस का क्या मतलब है।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister, Shri Patel.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): Madam, Chairman, I would like to thank the hon. Members who spoke on the Demands for Grants for the Home Ministry. I listened to their suggestions and criticisms with great attention. I welcome them because they shed light on what is being thought about various matters. The Home Ministry deals with so many different subjects. It was understandable that many of the hon. Members would want to speak on the subject and make some observations or other. But, in the main, their observations were confined to two or three major subjects—one was the law and order and the other about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Harijans and so on about the atrocities as well as what should be done in order to improve their lot.

Various local problems were also raised like those pertaining to Andaman and Nicobar Islands, Ladakh, Jammu and Kashmir and so on. You will see, madam, that several speakers really answered one another. For instance, in regard to Jammu and Kashmir, whatever my hon. friend, Dr. Karan Singh had said, was the position about Jammu, and it was answered in fairly full details by the other members.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Are you suggesting that you have accepted that? It is you who should answer and not the other hon. Members.

SHRI H. M. PATEL: There are several points of view. It is interesting to see that there was one point of view presneted and the other, a diametrically opposite one.

DR. KARAN SINGH: It is not so.

SHRI H. M. PATEL: All right. I stand corrected. A word was used there and my answer to that is this. It is another side of the picture presented slightly differently and immediately. And that makes the position very interesting.

I would, therefore, very much like that. Similarly, in regard to the law and order, if you will see, Madam, various speakers said that there was no such thing as law and order in the country to-day. Now, I think it is obvious that a statement like that is a gross exaggeration. If really there were no law and order in this country, all progress would have been utterly impossible. And yet I do not think that that is the contention of any hon'ble Member. A few days back this House voted with acclaimation the Demands for Grants for Defence. The members were satisfied with what was being done to ensure the security of this country. Soundness of defence arrangements depends very much on the equally satisfactory arrangement in the internal security and, therefore, I am very happy by implication the hon'ble Members have also accepted the position that generally speaking there is law and order in this country.

AN HON. MEMBER: It is rather far-fetched.

SHRI H. M. PATEL: My friend, Mr. Asoke Krishna Dutt, referred to an observation which was attributed to me. Soon after I took charge of this portfolio, I was passing through Calcutta and what I said was: I have just taken over and I have no knowledge of the detailed situation in the country. Then the journalist asked me, "No. You can say something from general knowledge. Afterall you are in the Cabinet". Then my reply was: "In that case, perhaps, if you do want me to say something I would say that the law and order situation is no worse than it was a few days

ago or a month ago." Therefore, I am afraid, his indignation with me of having given a certificate to West Bengal government about the law and order situation being satisfactory in West Bengal was not correct. He gave various instances of the law and order situation not being satisfactory in West Bengal. I will certainly take note of that position and get myself more fully informed. (*Interruptions*)

I would like to take some time over the very important issues raised by Mr. Kamath and, I think, we ought to consider those long-term issues. He referred to a number of matters. First of all he took up the question about the Lokpal Bill. The Lokpal Bill is almost ready for being presented in this House....

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Report has come.

SHRI H. M. PATEL: Report has come. Thereafter it has to go before the Cabinet and then form the Bill. I am hoping that it will be possible to present the Bill during this Session.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Not only hope but make sure.

SHRI H. M. PATEL: I would certainly like very much to do so but it is not easy to get the time.

Then he referred to the National Police Commission. The National Police Commission certainly submitted an interim report some time ago but it was submitted within a few weeks of my taking over the Home Ministry and I said that we will process the recommendations of that commission as speedily as possible. The final report will be coming along. (*Interruptions*)

In fact, the interim report submitted by the National Police Commission is a very interesting one and it covers very important issues. It has gone into this question that was raised by several hon'ble Members who said that the working conditions and the living conditions of the police should be improved. These have been dealt with therein. They have gone into the functions of the police, the way in which they work, why is it that they are a necessity and we must have them and what is it that we should do to see that we have a good police force. These are all the points which have been commented upon and we shall consider them and we shall come forward with appropriate decisions as speedily as possible.

Then there was the question of prison reform. I may say that that is a matter which I took up very early as soon as I came to know that the number of under-trial prisoners in this country is very appalling. I have called for a meeting of the Chief Secretaries of all States on Monday next to consider precisely this question of Prison Reform. Jail manuals have to be improved.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: About Haryana.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No interruption Mr. Jyotirmoy Bosu.

Not in the middle. Later on.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He does not mind it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Not just now. He is not yielding.

SHRI H. M. PATEL: I am not yielding. (*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He took the hint from the Chair.

MR. CHAIRMAN: Please sit down Mr. Jyotirmoy Bosu.

SHRI H. M. PATEL: I have a very limited amount of time. I want to finish it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You continue it. Don't take note of interruptions.

SHRI H. M. PATEL: Regarding under trial prisoners, we propose to tackle this by taking several measures. There will be administrative measures which will be taken. There will be legislative measures also. Among the administrative measures which we propose to take on is this. There are large number of persons who are undertrials and who continue for long as under-trials. The people among them who have resources go and ask for bail and go away. There are among them those who have no resources who cannot engage a lawyer and they could not get bail. Their number is quite large. A considerable percentage of those who are under-trials today are there only because of this reason. So, steps will have to be taken to ensure that this situation is remedied. This we are examining. I am quite sure that within a very short period of time we shall be able to deal with this.

Now, on the question of prisons themselves, the jails which we have in this country, were constructed in the 19th century....

AN HON. MEMBER: in Barracks...

SHRI H. M. PATEL: About 20 per cent of those that exist today were constructed in the first two decades of this century and therefore they are by and large not having what you call modern emenities. They don't have facilities and amenities—even the minimum amenities which have to be provided for these people. Although there is a provision in the Jail Manual about making separate provision for women prisoners, for children, for young people of a certain age, for juvenile delinquents to be separated and so on, none of these facilities exist, except in a few States—perhaps not even half a dozen States. All these points will have to be considered. Naturally all these things mean a good deal of money. The progress towards complete reform would necessarily take some time. This cannot be done overnight. But I am sure that we will succeed and I am confident that we will make a definite move in that direction.

Then, I think, references were made to the Shah Commission and a question was asked as to what action has been taken on the Shah Commission's reports. 19 FIRs have been completed and filed. Further progress will be made with regard to those cases.

Certain hon. Members made reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission and the Backward Classes Commission.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order....

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): It is 5-30 now. We have to take up the Calling Attention Motion with regard to the serious power situation in West Bengal.

MR. CHAIRMAN: I have already mentioned this earlier. Nobody took objection to it. I am asking the House to express their view. Do you agree to extend the time so that the Minister can finish his speech?

SOME HON. MEMBERS: No.

SHRI SAUGATA ROY: Many members want to ask questions on Calling Attention. They must have the time for that. You cannot extend the time of the Home Minister.

Madam, it is now 5-30 p.m. We have to take up the Calling Attention as listed in Business for the day.

MR. CHAIRMAN: This is exactly what I was asking as to whether the Calling Attention might be taken a little later, that is, after the Minister completes his reply to the debate.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, no. There is no question of the Minister continuing.

SHRI SAUGATA ROY: Madam, power situation is very terrible in Calcutta. There people are going without electricity....

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him complete his spech.

SHRI SAUGATA ROY: But you cannot extend the time of the House like that. I think you have to take the permission of the House.

MR. CHAIRMAN: The House has to decide this. The proposal is....

(*Interruptions*)

PROF. SAMAR GUHA (Contai): Why are you trying to hurry through? The Calling Attention is in my name. You have to ask me first whether I was agreeable to postpone it or not.

MR. CHAIRMAN: Now, You agree to delay your Calling Attention Motion?

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I cannot follow what is being said in this matter. I am to hear Mr. Samar Guha. I cannot hear what Mr. Saugata Roy says.

PROF. SAMAR GUHA: The reply of the Home Minister regarding the affairs of the country is very important. He should not hurry through the matter. We should not try to finish it within 15 or 20 minutes. We should do justice to so many points raised by hon. Members and therefore he should take more time to cover all those points. There are so many points and there are so many issues before this House. He cannot finish it in 15 or 20 minutes.

MR. CHAIRMAN: It is not the question as to what the Home Minister should do. The question is: Do you agree to delay your motion?

PROF. SAMAR GUHA: I do not.

MR. CHAIRMAN: Then I am afraid the Minister has to be interrupted.

SHRI H. M. PATEL: Should we continue after the Calling Attention motion is over.

SOME HON. MEMBERS: On Friday. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I do not think I can ask the House to sit after the Calling Attention.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Already 5 minutes are over. Therefore, we have to sit five minutes more. (*Interruptions*)

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं यह विषय भी उतना ही आवश्यक है। इसलिये इसके बाद थोड़ा सा अगर बैठ कर माननीय गृह मंत्री का जवाब सुना जाय तो अच्छा रहेगा ताकि और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो जाय। अन्यथा बहुत से अन्य महत्वपूर्ण विषय गिलोटीन में चले जायेंगे। इसलिये गृह मंत्री जी का जवाब होना भी आवश्यक है। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उनको इस स्थिति को समझना चाहिये और कोआपरेट करना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: Let me first dispose of one item. Then I would be able to say how much time the House would take.

SHRI SAUGATA ROY: I do not know why the Minister could not continue on Friday. I think he will be out of Delhi on that day.

PROF. SAMAR GUHA: I do not understand why the Home Minister should undertake any kind of programme outside Delhi during session especially when his Ministry's Demands for Grants are being discussed in the House. The Home Minister should take into consideration the importance of this House.

MR. CHAIRMAN: Mr. Guha, I have asked you to proceed with the Calling Attention.

DR. KARAN SINGH: Madam Chairman, some of us want to seek certain clarifications from the Home Minister after his reply. Will you kindly inform us whether the Home Minister will resume his reply after the Calling Attention is over today or on Friday.... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: I do not know how much time will be taken on the Calling Attention, and whether the House will agree to sit late thereafter. Let the Calling Attention be finished first. I am not in a position to enlighten you just now.

Prof. Samar Guha.

12.36 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(ii) Reported deterioration in Power supply in Greater Calcutta

PROF. SAMAR GUHA (Contai): Sir, I call the attention of the Minister of Energy to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Reported deterioration in power supply in Greater Calcutta and other parts of West Bengal and the difficulties being faced by the people as a result thereof."

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): Mr. Speaker, Sir, the power supply situation in Greater Calcutta and different parts of the State of West Bengal is showing signs of improvement after a spell of sudden deterioration during the last week of March, when the load shedding was to the extent of 230 MW. But this trend has now been arrested and the load shedding is in the range of 140 MW. Even this is a matter of concern to us.

The power requirements of the State of West Bengal are being met from generation from thermal power stations at C.E.S.C., Bandel, Santaldih, Durgapur Project Ltd., Gowripur, with hydro stations making a meagre contribution to the system. If there had been enough hydro capacity in the system, it could have helped a good deal to take care of the peaking requirement where at present there is acute shortage. The peak load and energy requirements of West Bengal is about 950 MW and 16 million units per day. But the system is not able to meet this as a large number of units are on forced outages and enough power is not being generated from other stations.

As per the West Bengal Energy Control Order of 1974 the demand of greater Calcutta has been assessed at 580 MW, but the availability has been only of the order of 460 to 520 MW. There are four agencies involved in the supply of power to Greater Calcutta, *viz.*, Calcutta Electric Supply Company, West Bengal State Electricity Board, Durgapur Projects Ltd., and Damodar Valley Corporation. While the generation in the Damodar Valley Corporation has picked up and are now generating to the extent of 700 MW, the generation at other stations supplying power to Calcutta is not what it ought to be. Even though in the month of February 1979 and most of the period in the month of March, there was a load shedding of 125 to 135 MW the power supply situation worsened towards the end of March when a large number of units went on outages. In the Santaldih power station alone where 360 MW of capacity has been created, all the three units were down thereby causing a major upset in the supply schedule for the system as a whole.